

certain matters to the notice of Ministers concerned so that if they want and think the matter to be an urgent one and if there is time available with the House they will reply. That object will be served by my communicating in a faithful and loyal manner whatever has been said by the hon. Members to the Ministers concerned.

MR. SPEAKER: He cannot reply on behalf of them. He will convey it to the Ministers concerned. This practice which has been evolved after all you do not make it so strict that you demand the reply just now. He will convey it to the Ministers concerned and they normally do reply.

श्री मधु लिमये : यह हमको जवाब नहीं दिलवाते, यही तो हमें शिकायत है। फिर कहा जायगा कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं। हम लोगों को तो जवाब चाहिए।

12.40 hrs.

FINANCE BILL, 1975—contd.

श्री चन्द्र शंलानी (हाथक) : अध्यक्ष जी, परसो वित्त विधेयक पर बोलते हुए मैं आर्थिक असमानता पर चर्चा कर रहा था : देश में जो आर्थिक असमानता है, गरीब अमीर के बीच में जो विशाल खाई है, छोटे बड़े का जो फर्क है और मालिक मजदूर का जो झगड़ा है, उसे समय रहते जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम ने भारत में सर्वसत्ता सम्पन्न लोकतंत्रत्मक गणराज्य की स्थापना की और देश के कर्णधारों ने, हमारे नेताओं ने समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया। समाजवाद एक महान सिद्धान्त है एक महान विचार है, जिसको आज आधी से अधिक दुनिया ने अपनाया है और अपने जीवन का अंग बनाया है और जिस पर चल कर बहुत से पिछड़े हुए देशों को, अंधकार में डूबे हुए देशों को एक नया जीवन मिला है, एक नया रास्ता मिला है और एक नई रोशनी मिली है और

उस पर चल कर उन्होंने चतुर्मुखी विकास किया है और दुनिया की दौड़ में आगे बढ़े हैं। हमारा भी यही संकल्प है, यही स्वप्न है और देश की प्रधान मंत्री और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का जीतोड़ प्रयास है कि देश में समाजवाद का पौधा फले फूले और एक दिन इतना विशाल वृक्ष बने जिस की घनी छां के नीचे बैठ कर देश की जनता राहत की सास ले सके। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार सही हो। आज हम देखते हैं कि सरकार जनहित में जो नीतियां बनाती है, पहले तो उस के रास्ते में बहुत से रोड़े अटकाने जाते हैं और जब सरकार उन का मुकाबला करके अपनी नीति पर दृढ़ रहती है, तो उस पर अमल नहीं हो पाता।

प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि बड़े-बड़े पूंजी वाद बैंकों पर हावी थे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि इस से गरीबों को, छोटे-छोटे उद्योग अन्धे करने वाले छोटे व्यापारियों को और पिछड़े वर्गों के लोगों को अधिक फायदा होगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से गरीबों को और पिछड़े वर्गों के लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ऋणदेने की जो नीति है, वह गरीबों के हित में नहीं है और वह इतनी पैचीदा और दावतच की नीति है कि उस का फायदा गरीबों को नहीं मिल पाता है और मैं यह कहे बगैर नहीं रह पाऊंगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गरीब लोग और छोटे-छोटे काम करने वाले लोग अपने धंधों के लिए बैंकों के दरवाजों पर ऋण लेने के लिए जाते हैं, तो उन के साथ सही सलूक नहीं किया जाता है और उन को फटकार दिया जाता है और कुछ अफसरों का परसेन्टेज बढ़ा हुआ है। वे कहते हैं कि हमें

इतना परसेन्ट दो, तो हम आप को ऋण देंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बैंकों की जो ऋण देने की नीति है, उस में वे सुधार करें और उस का फायदा ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को और पिछड़े हुए इलाके के लोगों को होना चाहिए।

अध्यक्ष जी, देश में बहुत बड़ी तादाद में करों की चोरी होती है। वैसे तो कोई भी मुल्क बगैर टैक्स लगाए चल नहीं सकता और देश की जनता की बहबूदी के लिए, देश के विकास के लिए कर लगाने बहुत जरूरी है लेकिन हमारे देश में जो हर साल कर लगाए जाते हैं, तो मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नये कर लगाने में पहले वे इस बात पर विचार कर लें कि कितना करों को टैक्स के रूप में अभी बाकी है। मैं आप को बता देना चाहता हू कि चाय बागानों के मालिकों पर आज भी टैक्स का एरियर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की तादाद में बाकी है और यह भी आप के माध्यम से मैं सरकार को बता देना चाहता हू कि वहां पर इन्कम टैक्स का एरियर अरबों रुपये की तादाद में बाकी है। फिल्म इंडस्ट्री वालों पर बड़े-बड़े पूजापतियों पर और बड़े-बड़े मालिकों पर टैक्स करोड़ों पर की तादाद में बाकी है और सरकार उस को वसूल करने के लिए भी कोई भी कठोर कदम नहीं उठा पा रही है जिस का मुझे अफसोस है और दूसरी तरफ— मैं एक बहुत पिछड़े हुए समाज से और पिछड़े हुए इलाके से आता हूँ— मैं यह देखता हू कि जब किसानों की फसल मार जाती है चाहे वह ज्यादा पानी बरसने से मारी जाए या सूखे से मारी जाए, तो तहसीलदार लगान वसूल करने के लिए उस को जेलखाने में डाल देता है, बन्ध कर देता है जबकि उस के जीवन का आधार यही है। तो ये छोटे छोटे लोग किसी वजह से जब सरकार का टैक्स नहीं दे पाते हैं, तो उन को जेल भेज दिया जाता है और बड़े-बड़े लोग, पूजापति लोग जो अरबों रुपये की टैक्स की चोरी किए बैठे हैं और सरकार का टैक्स भुका नहीं कर रहे हैं,

उन के ऊपर सरकार कोई सख्ती नहीं कर रही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरकार का जो रुपया कर के रूप में बकाया है, उस को सख्ती से वसूल किया जाए।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सेन्ट्रल एक्साइज गूड्स मैन्युअल डिफेक्टिव है। देखने में यह आता है कि इन्कम टैक्स एरियर्स के ऊपर तो व्याज लिया जाता है लेकिन सेन्ट्रल एक्साइज के जो एरियर्स हैं, वे व्याज मुक्त हैं और उन पर कोई व्याज नहीं लिया जाता है। इस में सुधार होना चाहिए।

प्रब मैं एम० आर० पी० पर आता हूँ। एम० आर० पी० को खत्म कर देना चाहिए। इस में कोई फायदा नहीं है। इस से सरकार को कोई फायदा नहीं है बल्कि इसमें उत्पादकों और मिल-मालिकों का फायदा है और बड़े बड़े पूजापतियों को फायदा है क्योंकि इस में उन को वहना मिल जाता है। जिनका मान वे पैदा करते हैं उस की गली गम्भीर सरकार के नामने नहीं जाती और मही मूल्यांकन सरकार को नहीं हो पाता इसलिए इस को खत्म कर देना चाहिए। मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि वे फिजिकल कंट्रोल को लागू करें।

अध्यक्ष महोदय, कभी कभी अच्छे कामों में फानून भी रुकावट बन जाते हैं जैसे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया था तो सुप्रीम कोर्ट आड़े आया। आज जब देश में तस्करी के खिलाफ एक अभियान चला और बड़े-बड़े तस्करों को जेलों में डाला गया, तो फानून आड़े आ गया। वे तस्कर जो करोड़ों रुपये की तस्करी करते थे, और भारत सरकार को करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का नुकसान पहुंचाते थे, वे आज जेल से बाहर हैं और जिस धंधे से निकल कर आए थे, उसी धंधे में फिर फंस गए हैं और फिर वे सरकार को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि यह देश का सर्वोच्च सदन है, इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि फानून में भी सुधार किया जाए।

अध्यक्ष जी, अब मैं तन्खवाहों पर आता हूँ। आज हमारे देश में 5 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक आदमी की तन्खवाह है। एक समाजवादी देश का लक्ष्य यह है कि समाजवाद हो और देश में जो इतनी बड़ी अममानता है, वह ठीक नहीं है। एक गाँव के चौकीदार को आप देखिए। अगर रात में डकैती पड़ जाए और कत्ल हो जाए, तो वह आनी जान हथेली पर रख कर थाने में आना है लेकिन उसको 5 रुपये तन्खवाह दी जाती है अर्थात् देश में लोगो को चार-चार, पाँच-पाँच और दस-दस हजार रुपये तन्खवाह दी जाती है। समाजवादी देश में होना यह चाहिए कि 1 और 10 की रेशो हो और इस पर प्रत्येक आप अमन नहीं कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 और 20 की रेशो होनी चाहिए। हमें इस में कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है कि किसी को 10 हजार रुपये तन्खवाह क्यों देने है। अगर आप 10 हजार रुपये तन्खवाह देने है तो मेरा आप से इतना ही निवेदन है कि एक गरीब मजदूर और शोषित वर्गों के जो मजदूर माने हैं उनको 1 हजार तन्खवाह दे या 500 रुपये तन्खवाह दे। इतनी तन्खवाह तो उन्होंने जरूर देनी चाहिए, यह मेरा आप से निवेदन है।

आज देश में जो आन्दोलन चल रहा है, इससे देश को आर्थिक क्षति हुई है। वैसे ही हमारा देश बड़ा गरीब है लेकिन अभी जो जी० पी० साहव आन्दोलन चला रहे है, उस आन्दोलन में काम करने वाले लोग जगह-जगह पर तोड़-फोड़ करते हैं और राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ता है। कहना यह चाहिए कि इन आन्दोलनों की वजह से देश की अर्थ-व्यवस्था चकनाचूर हुई है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को और सरकार को कि जय प्रकाश जी के या दूसरे आन्दोलनों में जितना राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान होता है, उस का मुआबिका उन से लिया जाए, वह जय प्रकाश जी से वसूल किया जाए। जय प्रकाश जी के पास

आज पैसे की कमी नहीं है। लोग उनको चन्दा दे रहे है और कौन लोग चन्दा दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जो करों की बोरी करते हैं। ये बड़े बड़े पंजीपति और बड़े बड़े उद्योगपति है जोकि लाखों की तादाद में सरकार की टैक्स नहीं दे रहे है बल्कि जय प्रकाश जी को चन्दा दे रहे है। इसलिए तो राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है, उसको जय प्रकाश जी से वसूल किया जाए। मैं आप से यह मांग करना चाहूंगा . . (व्यवधा।) . . । अध्यक्ष जी, जब हम तरह की बात है, तो मैं यह कहै बगैर नहीं रह पाऊंगा कि आर्थिक क्षेत्र में जहाँ पर प्रगति हुई है और जितनी प्रगति उद्योग धंधों में हुई है, वहाँ पर बड़े-बड़े शहरों में हुई है। यह प्रगति अब थोड़ा सी गाँवों को भी जानी चाहिए, देहातों को भी जानी चाहिए। जहाँ पर 80 प्रतिशत लोग रहते है और जहाँ पर देश के गच्चे भाड़ने में निर्माता रहते है। चाहे तन्खेन में हल चलाते हो या कारखानों में काम करते हो और कोई शारीरिक परिश्रम करने हो। इन देहातों में उद्योगधंधे खोलने के लिए वित्त मंत्रालय को कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बड़े-बड़े उद्योग धंधे देहातों में, छोटे-छोटे कस्बों में खोले जाने चाहिए।

मैं एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आता हूँ, हाथरस। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जबकि भारत की आजादी के बाद छोटे-छोटे गाँव कसबे बन गए हैं, कसबे नगर बन गए है और नगर महानगर बन गए है, हाथरस ऐसा बदनसीब शहर है जोकि आजादी मिलने से पहले उत्तर प्रदेश का कानपुर के बाद दूसरे नम्बर पर आता था और जहाँ पर बहुत से उद्योग धंधे थे, अनेक मिलें थी, बहुत से लोग वहाँ काम धंधों के लिए आते थे लेकिन आजादी के बाद उसकी अवनति हुई है और वहाँ के उद्योग धंधे सब नष्ट हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि आप प्लानिंग कमिशन से सलाह मशविरा करके हाथरस क्षेत्र के लिए

एक साथ बड़े से बड़ा उद्योग दें ताकि पिछड़ी हुई जनता को रोजी रोटी का साधन मिल सके।

मेरा आप से निवेदन है कि आप मेरी यह हार्दिक भावनाओं वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री जो स्वयं उपस्थित है उनके माध्यम से—वित्त मंत्रालय के जो बड़े-बड़े अफसर हैं उन तक पहुंचा दें कि वे देश की नब्ज को देखें, बख्त की मांग को पहचानें, वक्त के तमजे को देखें और उसके मुताबिक आर्थिक सुधार देश में लाएं। समझ रहते जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करें। आज पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं जिनका अभी मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया था, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के बहुत से लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, धंधा नहीं है, जमीन नहीं है, जिस की वजह से बड़े-बड़े पैसै वाले लोग, जमींदार लोग उनका शोषण करते हैं। यह इस बीसवीं शताब्दी में विज्ञान के युग में और आजादी के 27 वर्ष के बाद भी हो रहा है। जब वे अपने लिए लड़ते हैं तो बड़े बड़े लोग, जमींदार लोग, पूंजीपति लोग उनको मारते हैं और इतना मारते हैं कि उनकी जान तक निकाश देते हैं। जब तक आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी आर्थिक रूप से पिछड़ापन दूर नहीं होगा, आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक ये जुल्म और अत्याचार भी समाप्त नहीं होंगे। इस वास्ते इस और विशेष ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो चन्द सुझाव मैंने दिए हैं उन पर वे अमल करें ताकि जन-हित में कुछ कार्रवाही हो सके।

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Before I enter into the Finance Bill, at the outset I should like to bring to the notice of the House about certain specific and very important features of our fiscal policy. The fiscal and monetary policy should be directed to achieve certain objectives: self-reliance, increased production with social justice, In-

spite of all our efforts we find here and outside, in reality, there is a big gap between promise and performance. Take for instance agricultural surplus land. 36 lakhs of acres are there. That had been given by the Land Reforms Commission. But what about their distribution? You find a gap between surplus land the its distribution. Similarly, take the Constitutional amendments. We have made basic constitutional amendments; they are really very progressive and they are meant to minimise and eliminate concentration of wealth in the hands of a microscopic minority, the few who go by the name of monopoly houses but in the world literature it has found a name as a citizen. Everywhere you find the same gap. Even Constitutional amendments have been made, but after that there is no follow up action. Similarly take for example direct and indirect taxes. Most of the Members of Parliament, even on the other side, have been pointing out that our tax burden on the Tatas and Birlas is not heavy whereas on the other hand what we find is that the indirect tax burden is a direct burden on the ordinary consumers and the poor people among whom 72 per cent are below the poverty line. They are made to bear the heaviest burden. You can also find this from the expression of the people. When I went to my Constituency some time back, I found that there was absolutely no drinking water. We are talking here about socialism, we are talking here about elimination of monopoly, capitalism and so many tall talks are going on and specially when we discuss the Finance Bill which has the relevance with the budget and also the Economic Survey and all these things we find that the gap is widening and widening. People put me a question: Where is the drinking water? Today it is not my experience alone. Here I quote the relevant news item that appeared in "The Times of India".

"The Chief Minister, Mrs. Nandini Satpathy today said that there

[Shri D. K. Panda]

was acute water shortage in all six blocks of Nawapara sub-division of Kalahandi district where the drought situation was very serious. Talking to newsmen on her return from a visit to the affected areas she said that even big tanks and wells had no water. It was a pathetic sight'.

I need not go into all these things, but I would tell that the people in the same Kalahandi district have started selling their children for a morsel of food to save their life and as Members of Parliament, representing about 7 to 10 lakh people each, we talk and talk and talk and here the ruling party turns its deaf ears. We simply talk and do nothing. The result is nil. So what I want to say is that the Parliament is becoming somewhat, I feel, sincerely, irrelevant, because from the very budget you will find that the Economic Survey suggests certain things. It has to review the budget performance. Once the budget is passed then the question comes how it has been performing. So, again we have to see what is the result. After that we have to examine the results as to how far our performance has been good. Then only any discussion on Finance Bill or budget or on the Economic Survey will be helpful as to whether the result is fruitful or not. But that is not done. Moreover we find that nobody is attaching so much importance to our discussions inside this House as far as the poor people outside are concerned. They are passing through a critical time and the entire country is passing through a deep economic crisis. So, under such circumstances, when we are discussing the Finance Bill, at least those points which are raised by the hon. Members in this august House should be heard. The Minister should answer the questions raised by the hon. Members. At least I demand that they should be answered.

Take for example the question of sugar nationalisation. 300 MPs have

signed a Memorandum and thereafter there was a Seminar in which about 62 MPs belonging to both Congress and the communist parties and other parties had participated in the deliberations. But when the demands for grants of the Ministry of Food & Agriculture were discussed in this House, not a single answer either from the hon. Minister, Shri Jagjivan Ram or Shri A. P. Shinde was given and they were telling that it was under the active consideration of the Government. What does it mean? Are you not turning a blind eye towards the sugar barons who have been looting and started a 'trinity' attack on the consumers, workers and cane-growers? In spite of the fact that 300 members of Lok Sabha have given a memorandum, there is absolutely no answer. After the Bhargava Commission recommended nationalisation, what have you done? No further callousness can be tolerated by the people outside. You have to take certain positive action to see that the poor people get rid of all these miseries. The people are facing a show death. In the case of Orissa, they are actually facing starvation death.

If the malady is properly diagnosed, the correct prescription will follow. But that has not been done so far. Take agricultural development. The Finance Minister had expressed some complacency about certain things. I quote from the *Economic Survey, 1974-75*:

"There is considerable evidence to suggest that India's agriculture seems to have lost the momentum, for growth it exhibited in the late sixties."

The output of foodgrains is not likely to cross the level of 103.6 million tonnes due to uncertainty in fertiliser availability and steep rise in prices of inputs. In part A of his budget speech, the Finance Minister has said in para 3.5.

"The Government has succeeded in combating the runaway inflation and also the food position is bright."

The Centre should not be so complacent. Mr. Shinde has declared here that the import of foodgrains should come to zero. But that is not going to happen. We have to import 5 million tonnes minimum. It is not confined to Rs. 295 crores, but it is Rs 500 crores. Some economists say it will go up to Rs. 1000 crores. How can you remain complacent that the food situation has eased.

In Orissa, the deficit to the tune of 20 lakh tonnes due to drought. There is a brochure on the activities of the Food and Civil Supplies Department which says:

"during the discussion at Chief Minister and Minister's level at Delhi about the shortfall in production of foodgrains in this State and the imperative need for the supply of adequate quantities of rice and wheat from the Central Pool to tide over the scarcity condition. The situation will have to be however, largely managed by increasing the quota of wheat."

So, they are totally depending upon the Centre now because of the drought. The Chief Minister has said today:

"That stray cholera cases have been reported but there have been no death due to starvation. the price of rice has gone up from 2.50 to Rs. 3.50 per kilo."

Just after the harvest season when in other areas something has been produced, how the rice per kilo has gone up to Rs. 3 or Rs. 3.50. This was admitted by the Chief Minister himself. As far as reality is concerned, it has gone up to Rs. 4 per kilo. As far as Ragi is concerned which is a staple food in my Ganjam District, it is selling at Rs. 3 per kilo. This was the cheapest food ever known in the history of the world. So, this complacency has to be given up. If

there is some proper review in the economy or in the budget, then only you come to some conclusions. Why are you avoiding the review? Only for the specific reason that you will be caught red-handed..

Take for example, socio-economic problem. It has been said times without number that land reforms have to be implemented. As far as the implementation is concerned, what have you done? We find that 2,16,244 acres of land is considered to be surplus though according to the Land Reforms Commission it is 36 lakh acres. I draw the attention of the hon Finance Minister that 36 lakh acres of surplus land has been actually stated to be surplus by the Land Reform Commission. Out of that 2,16,244 acres is considered to be surplus by the Government and out of which only 19,557 acres of land has been distributed. In Orissa, not even an inch of land could be distributed so far. In four other States, Ceiling Laws have not been amended at all. Therefore, what I want to say is that this land reform has to be implemented. If you are not going to implement the Ceiling Law, it will remain a scrap of paper. Then at it is the duty of the Kisan Movement, the Kisan Organisation to march forward and by their own strength they will go on implementing the Ceiling Law and then the surplus land will come into light and it will be distributed if the Government remains silent. Therefore, I give this as a warning. By virtue of their own strength and unity, they will definitely march ahead to distribute those lands and implement the Ceiling Laws.

Now let us come to the prospects in the industry. What is the industrial growth? What has been the target? The target in 1974 was 8.8 per cent growth rate. But what is the actual rate of growth? It has not reached 3.8 per cent even. Therefore, what we find is that there is now sliding back; there is retreat. There are concessions given to the monopoly houses.

[Shri D. K. Panda]

Now, take for example our attitude towards the public sector. The Industrial Policy Resolutions has categorically stated that India should have the mixed economy, the public sector undertakings should be given importance and should be allowed to expand. But what is our approach today? Scooters India Limited has been a sell-out. I have with me an invitation of Scooters India Limited. It is somewhere here.

MR. SPEAKER: He need not search for it. His time is over.

SHRI D. K. PANDA. At the end of the invitation it is written "Tata Press Limited". What has Tatas to do with Scooters India Limited, which is a public sector undertaking? This shows that Scooters India Limited is a sell-out. Is it printed with Tata's money or Government money? If it is Government money, why should they pay Tata, even if it be only Rs. 1,000 or Rs. 2,000? Why should Tata enjoy at the cost of the nation? This is another instance of pampering the monopoly houses.

In the FICCI meeting they hailed the policy of the Government, because you are drifting away even from the so-called mixed economy concept. We can understand the joint sector under the Industrial Policy Resolution. But what is this national sector? It is a dirty and totally clumsy bluff. I will not go into the details. It is said that 49 per cent of the people's money will be invested there and it is better than the joint sector, it is claimed now. So, Pai-Subramaniam formula tallies exactly with the views of Tata and Birla. To put it in the proper perspective, that Pai-Subramaniam-Tata-Birla formula has produced the national sector. Here they are out to plug the public sector. Only Rs. 2 or Rs. 3 crores were needed for this Scooter (India). Could they not find the finance for it? In yesterday's paper we find that 800 k.g. of gold was seized in the Jaipur palace. A part

of that would have been enough to finance this Scooter (India) Ltd., but under the Pai formula they are surrendering to the private sector and as far as the loans, tax arrears etc., are concerned, they are given more and more concessions. This is a distortion of the Industrial Policy Resolution.

The weaker sections should be given more financial help.

MR. SPEAKER: Your time is up.

SHRI D. K. PANDA: I have spoken only for 15 minutes.

MR. SPEAKER: No, No. I know it better.

SHRI D. K. PANDA: Another ten minutes please.

MR. SPEAKER: No, no.

SHRI D. K. PANDA: The outstanding loans by nationalised banks to 17 top monopoly houses stood at Rs. 582 32 crores, i.e., 15.2 per cent of the total loan advanced, as on 28th December, 1973. On 29th June, 1973, advance to five big business houses, including Tatas and Birlas, was Rs. 186 10 crores. Between October, 1973 and April, 1974 the public undertakings got a loan of only 10.8 per cent, while the large private houses and the trade sector got 36.4 per cent.

I would now like to point out how the Government is dealing with tax-evaders and those committing economic offences, how Government have defaulted in combating the economic crisis. Last year the anti-smuggling drive was started. We all welcomed it, but now what has happened? Due to inherent defects, now they are going to be released. Some have already been released by the Delhi High Court. So, the hon. Minister should at this stage reply to this question as to what they are going to do with the recommendations of the Seventy-fourth Report of the Law Commission which was submitted in 1972. Is it gathering dust?

None of the recommendations has been implemented so far. They have recommended a constitutional amendment to enable the arrest of smugglers, hoarders, blackmarketeers and foreign exchange looters and to confiscate their property, as also the setting up of special courts to try such offenders. At the end they have said that smugglers should not be allowed to have any remedy in courts, that they should not be given the same fundamental rights as others under the Constitution. We can put an end to hoarding, blackmarketing etc., only if there is a special law. Government is following a dilly-dallying policy with regard to smugglers.

MR. SPEAKER: Suppose your note is too long and the time is too short. What to do then? After all, we go by the time limit.

SHRI D. K. PANDA: I have carefully gone through the debate. I am putting specific questions.

MR. SPEAKER: There is no time. You have much exceeded your time limit. Your party gave three names. You have taken the time of all the three Members. The problem is that now you are taking the time of other parties.

SHRI D. K. PANDA: I was not here for the last one and a half months.

MR. SPEAKER: It is not their fault.

SHRI D. K. PANDA: I will finish in five minutes.

MR. SPEAKER: Not five minutes. Two minutes please. Every time you ask for five minutes, ten minutes. What is this?

SHRI D. K. PANDA: The tax evasion cases in regard to the Bajoria, Jalan and Birla houses have been reopened. That is a welcome feature, but at the same time, now what is going on? Now, they are allowed to go to the court. So far as 135 wealth tax cases are concerned, now, they

have gone to the Calcutta High Court. Now, the hands of the Income Tax Department are tied down and they are not in a position to do anything. Why should the Government be helpless in dealing with such cases when they have got the right to go the court and see that the entire thing is sabotaged. Therefore, special measures should be taken to see that these things are set right.

As far as the production is concerned—as far as industrial goods are concerned—I warn the Government that there should not be any reversal of this policy, and we have to continue our efforts to active self-reliance. In this country, power, shortage is stated to be one of the causes of decline in production.

As far as Orissa is concerned, there are three projects like Talcher Super Thermal Power Project, Indravati, Upper Kollab and Bhim Kund. All these are centrally sponsored projects. If finance is given to three-four States who will be in a position to supply power, there would be no difficulty. Therefore, I suggest that these projects should be taken up by the Centre.

As far as electricity is concerned, Government has to give special attention to it.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Mr. Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me. The Finance Minister in his Budget speech has stated, "I have done my best to reduce the minimum burden that would fall on the vulnerable sections of society." Though this has been a very pious hope on the part of the Finance Minister, the way in which the tax measures have been drawn has not justified the hope that has been raised by the declaration made by the Finance Minister. Out of a total additional taxation measure of Rs. 289 crores, more than 98 per cent has fallen under indirect taxes which account for the maximum burden that can go to the consumers in this country. Indirect tax on sugar, textile, tea, etc. pushes up the prices of the basic commodities

[Shri Sezhiyan]

thereby affecting the common man already suffering with the burden of taxation. In an inflationary environment, indirect taxes are inflationary. I do not know, for what reason, this Government again and again in an atmosphere of inflation deals with a very heavy dare of indirect taxation which goes to aggravate the situation already obtaining. Also in the Budget speech the Finance Minister has set out some priorities. He has said that agriculture, irrigation and power will be given the highest priorities. Though this is a laudable and a welcome wish, it has remained a wish.

13 25. hrs.

[MR. DEPUTY -SPEAKER in the chair]

If you go into the Central Plan provision in the Budget for the year 1974-75, you will find that the provision was Rs 2,055 crores whereas the provision for 1975-76 has gone up to Rs 2,558 crores; it shows an increase of 24 per cent in the total outlay, of which the outlay for Agriculture and Allied Services which was to the tune of Rs. 216 crores in 1974-75 has gone up to Rs. 227 crores in 1975-76; the outlay for Water and Power which was Rs. 99 crores in 1974-75 has gone up to Rs. 117 crores in 1975-76. In 1974-75 Agriculture and Allied Services constituted about 10.5 per cent of the total Central outlay whereas in 1975-76 it has gone down to 8.9 per cent; the percentage for Water and Power which was 4.8 in 1974-75 has gone down to 4.6 in 1975-76. Even though the Finance Minister started his Budget speech saying that they are going to give the highest priorities for Agriculture, Irrigation and Power, the Central Plan provisions have been going down with reference to percentage of the total outlay.

Incidentally I want to raise the pitiable condition today to which the City of Madras and other places have been brought. The State Government, by themselves, cannot solve this problem because it is about Rs. 100 crores and Rs. 200 crores. These

schemes have to be sent to the Centre, and the Centre takes its own time so much so there have been avoidable delays. If those delays had been avoided, we could have got out of the present crisis. I lay the blame for this squarely on the Central Government for not visualising these things. It is said that a statesman should be a person who anticipates a problem before it becomes a crisis, and who anticipates the crisis before it becomes a catastrophe. In India we never try to solve any problem. One crisis comes and another overtakes it. We forget the earlier crisis and try to solve the coming crisis and the coming crisis will be overshadowed by some other crisis. We never solve any crisis, but only allow another crisis to overtake it, so much so accumulation takes place.

Perhaps the Finance Minister may believe in this that money will not produce water and that is why, perhaps, he does not allow Central outlay so much on water and irrigation.

I now come to the concessions that have been announced by the Finance Minister the day before yesterday. He has announced concessions to the tune of Rs 33 crores. I am not an expert in this. I went through it but could not find out the break-up of Rs. 33 crores, under which items he has given larger or smaller share; whether the larger share will go to the poor and the vulnerables or to the rich and the venerables, I do not know whether the largest share out of the concessions that have been announced by him will go to J. K. Synthetics or the Modipan or Vimal. I do not know. Before the Finance Minister speaks, I would like the break-up of the Rs 33 crores concessions which he has announced on the 30th April, to be given to this House so that this House and the country could know who would be the beneficiaries of these concessions.

In the speech that he made on the 30th April, the Finance Minister has said, "We shall maintain the tempo of anti-smuggling". Here I have my own

doubts whether this has been proved or this has been put in practice. Only last month, that is, in the month of April, many of the known persons who were caught as big smugglers like Mr. Bhatia, Mr. Yusuf Patel and others have been ordered to be released by the Court. The Court has delivered the judgement. There are two or three disconcerting places in the Court's observations. If I take the judgment alone, then I will charge this Government that they have been very complacent, if not conniving at the release of these smugglers. In the judgment that has been given on 18th April by the Division Bench of the Delhi High Court this has been stated at one stage. They had said that the charges under which these persons had been taken into custody were fabricated and concocted that was the charge raised by the other side. And the court wanted certain particulars to be given to it to judge the issue and the counsel who represented the Government failed to put the affidavit so much so that the court has mentioned in its judgement:

"We had given it an option to place relevant material before us to enable us to judge whether in fact the report of the Customs officials relied upon was in existence since August 1974 and looked into by the detaining authority. It is unfortunate that relevant record was not placed before us."

If this is the approach of the Government defending itself in a court and they did not make an affidavit there which was called for by the court, I think, I will find it very difficult to resist the conclusion that the Government itself wanted the releases to be made for reasons, I do not know. One of the newspapers, *Economic Times* has made a guess: it is only a guess work. This paper cannot be said to be an anti-Government paper. It said under the heading 'Smugglers: Government in a Fix':

"The government's discomfiture is all the more acute because the High

Court while upholding the constitutional validity of the legislation had released the detenus on the plea that the grounds under which they were arrested were either non-existent or vague. While the Government is likely to face severe criticism in Parliament for not making out a water tight case against the detenus, more particularly also because the court had passed critical remarks on the Finance Minister for not filing an affidavit, it could still plead that it had done its utmost to bring the smugglers to book."

During the last 6-7 months, the Government is taking all the credit for using all their weapons, even the Emergency was said to curb the anti-social elements and economic offenders. When the Government is tuned to that, why the Government fails to put an affidavit to give the necessary evidence before the court, so as to invite remarks from the High Court. The Special Correspondent of *Economic Times* has ended his Article Smugglers: Government in a Fix like this:

"The Government at the same time is vulnerable to the charge of conniving with the smugglers, particularly because the elections are round the corner."

This is a comment by the paper. Whatever it is worth, I am giving it to the House and to the Minister.

I am one with the Government that these smugglers and anti-social elements should be brought to book in the normal way of law taking its own course. This is not the first time that the Government plea has failed in the court. After the case of Chawla, Government wanted certain things to be done. When it considered that evil practices are affecting the conduct of elections, immediately they brought an ordinance to protect the other cases. In this case, why not take some immediate steps? Why not issue an ordinance so that all the fellows who are out, and whom the Government con-

[Shri Sezhiyan]

siders anti-social are brought into the net.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Ordinance when we are sitting?

SHRI SEZHIYAN: Why not bring it before the House? You can have the legislation passed in a day. This House would have come to the rescue of the Government. In this case, they would not come. When we do not want, they would bring so many things.

I have read in the newspaper today that they are taking special appeal to the Supreme Court. As you are aware, the Supreme Court would adjourn its session on 5th May. If they do not move quickly and get something done they will not be able to do anything for two months. By the time, probably elections in Gujarat will be over and many of the problems might have been solved for both side.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) I would like to clarify the position. In fact, going to the Supreme Court was not left to us. We appealed before the Delhi High Court for a special leave to appeal before the Supreme Court. As soon as Delhi High Court gave the permission, immediately we rushed to the Supreme Court. This is precisely the position.

SHRI SEZHIYAN My apprehension is that the courts are going to end their session on 5th May. Unless you take immediate action, these persons whom you want to get into the net will be very free and we know, how many years it will take to get them again. Unless you take this House into confidence, and make statutory provision, the mischief will be done. The other day, you are aware, I raised a question of legislative competence regarding the 1 per cent General Commodity Tax. At that time, my aim was not to stall the

consideration of this one. Even now I sincerely feel the way in which the General Commodity tax of 1 per cent is being introduced, cannot be done under the charging Section 3 of the Central Excise Act. Still I feel so, because, unless the items are specified as per the definition in Section 3, it cannot be put in that Schedule I. That is one submission I want to make.

Then, if you take the Customs Act, there, the charging Section is, I think, Section 12. There, the provisions are very clear. There, they say that all goods imported or exported come under the purview of the Customs Act. Therefore, if you put a Schedule and take about 10 or 15 items and say that all the other items can be brought under that charging section, that cannot be done. Here, the charging section under the Central Excise Act is a specific one. It says that only those chargeable goods, the goods listed and described in the Schedule can be put. You cannot put undescribed ones. All the other items you cannot put into that. I again request the Minister not to get angry with me because persons who go to court should not get angry in the same tenor that he gets angry with me. Therefore, I appeal to him to consider the basic thing, that these things cannot be brought. Here, I want to make it clear. This House is competent to levy a tax and to give sanction to levy a tax, but not in the way in which it is now being done, because, when we make a legislation, they should take, in the fitness of things, as they are available now. Had they brought a separate measure as Gift Tax or Wealth Tax, all these things could have been absolved.

I am told that this is based on the Valued Added Tax which is in vogue in some of the European countries. There, it is neither a sales tax nor an excise duty. It is combined. If it is a new concept, why don't you come out with a fresh legislation, putting this thing in a clearer way, without any puzzle or without going into in-

fructuou_s exercise of including it into the excise duty. That is my appeal to him.

I would also like to know how this Rs. 24 crores was calculated. What was the basis for the expectation of Rs. 24 crores. You say that all commodities are being brought into this one. There are 40,000 crores or so of the general national products. You leave out the agricultural products and other things. Even then 18,000 or 20,000 crores will be there and at the rate of 1 per cent, you should get Rs. 180 or Rs. 200 crores even if you omit all the other items. I want to know on what basis this Rs. 24 crores was arrived at.

There is a lot of confusion in the 1 per cent General Commodity Tax because, as I said the other day, the Finance Minister, when he made his speech, made this observation. Regarding the new concept of the General Commodity Tax of 1 per cent he said, 'This will cover all the goods produced for sale or other commercial purposes.' The other day when I referred to this one, somebody—I think it was Mr. Salve or the Finance Minister—said, 'Don't talk of my speech. Talk about the Bill.' The speech of the Finance Minister was not an off-hand speech. It was a prepared speech, well-written and a well-thought-out one which comes only once a year along with the Budget. In that one they have said, 'This will cover all the goods produced for sale and other commercial purposes'. You take it from me that in Supreme Court cases it has been very well held that excise duty will cover only those goods manufactured without any reference to sale or and without any reference to the commercial purposes. If you are putting 'for sale or commercial purposes', then you will be open to the charge that this is another kind of Sales Tax which can come only under the States' List and not under the Central List. This is the confusion that has been created by the Minister himself in his Budget speech. Then,

a Finance Ministry's spokesman, briefing the Press on March 1, 1975, a day after the presentation of the Budget, has gone on record saying—it has been quoted in the papers—'It will be based on returns made by producers of particular goods.' If you are going to say 'particular goods', why are you having all the commodities? Then specify the particular commodities? If it is 100 or 50, put them in the First Schedule. Now we have already got 123 goods there. Why don't you put another 50 goods? This sort of a haphazard and confused way of putting a tax is going to defeat the very purpose. There are thousands of products and thousands of factories in this country, and unless those factories are all registered and licensed under the Excise Act, they could never come under the purview of this one. You are bargaining for more trouble than you are able to solve in this one.

I will talk about two more subjects. Whenever we make a legislation for all commodities, then, what will happen? They will have to exempt one by one. They have to exempt so many things. You cannot specify them. If you exempt one, then you may say exemption on such and such will not. This kind of exemption is one of the worst systems that can be available for a tax administration.

I want to refer to SRP (Self Removal Procedure) Report. It is a new concept introduced by the tax administration a charter headed by Shri B. Venkatappiah. It is a very good report. In that they clearly analysed the dangers and mischiefs done by exemptions. Page 44, Chapter 6 of their report states:

"Barring a few exceptions, the exemptions notified cover the entire gamut of Central Excise. We are told that there are nearly one thousand live notifications today (in addition to 59 which are described as otiose) by virtue of which duty reliefs are afforded. . . .

[Shri Sezhian]

It appears that some three hundred tariff rates have, as a result of the issue of notifications of exemption, been multiplied into more than two thousand effective rates."

Unless the tax authorities remember 2,000 effective rates they will not be able to charge correct rate.

On page 50 of the same report, it has been said:

"It is generally agreed that schemes of exemption provide considerable scope for evasion and avoidance of central excise duties." Therefore, I request the Minister not to indulge in tacking an omnibus and apply the exemption which will reverbrate and will be open to abuse and also cause accusation that the Government has not done it properly

I would now come to taxation proposal regarding skelp coming in Clause 37. Something has been done in a scandalous manner. The Indian Tube Company, Jamshedpur, a subsidiary of the TISCO—has been producing iron tubes out of the sheets given by TISCO. The iron tubes can be made out of Skelp or out of hot-rolled sheets. Previously, there was no difference in the rates of duty levied on these two items. In 1964, the rate of Skelp was made higher than the hot-rolled. TISCO evaded the increase in the tax by giving their returns stating as having produced and given hot-rolled strips. But they collected from the Indian Tubes at the higher rates applicable for skelp. The Indian Tubes on their part passed on these increased collections from the consumers, out of whom Government of India was a major consumer. In 1964, the Excise Department found out this and attempted to collect the increased rate applicable for Skelp, as the TISCO has been collecting that

amount of rate from the Indian Tube. But in 1964, TISCO obtained a stay from the Delhi High Court. From 1964 to 1975 the Government did not make any serious effort to evict the stay order with the result at least Rs. 12 crores are now in arrears under this item from TISCO. Audit and the Public Accounts Committee took a serious notice of the complacency of the Government. As was expected, the appeal to the Supreme Court also failed. Rs. 11 to 12 crores is the tax as per calculations at a higher rate. I would like to know from the Finance Minister:

- (1) What were the difficulties of interpretation experienced by Government?
- (2) What was the total arrears claimed from the TISCO (My information is at least Rs 12 crores).
- (3) Whether any interest becomes chargeable on these arrears. (otherwise the interest from 1964 will almost be equal to the arrears)
- (4) The taxation proposals in the Finance Bill come into operation immediately after its introduction, i.e. from 28th February, 1975 onwards. Under this provision, what steps have been taken by Government towards collection of these arrears; whether any notice has been given under this provision?

Then, regarding the gratuity clause, I wish to say something. I have got a long list, but I will speak only points I feel this, that the workers are not getting the protection that they seek. The dishonest persons have been getting the tax-exemption by not creating the approved General Provident Fund and Superannuation Funds and they are doing all these things in such a way that the workers are not getting the benefit and the workers are left without any protection. That is why

the new Clause 6 is put in there. Instead of plugging the loopholes, they have opened it wider, by positioning the date to 1st April, 1976. Why cannot you have this Clause—'Notwithstanding any judgment'—as you have put in Clause 37? The same thing 'Notwithstanding any judgment' could have been put in here. Why not you do it? What happens to those companies which got the tax-exemption but have not created the approved GPF? You have set the date as April, 1976. Even there you have been feeble in saying that only an application should be made before 1st April, 1976, but not the approval. Please see the amendment given by the Minister. It is stated that only application should be made, not the approval of the Trust created. If the Company goes into liquidation before 1976 all the workers will be left in the streets.

Therefore, Sir, what I feel is this. This is more to help the big employers who have been dishonest in misappropriating the gratuity funds for their own benefit, deceiving the tax authorities, by taking the tax exemptions, and not creating the approved Provident Fund.

Then, regarding the SRP Report. I would like to know why that Report has not received the serious attention of the Government, that it should have received. This was given in November, 1973. This report is still in stencil form and it has not been printed and circulated to Members.

Then, regarding the concessions and other things, as I have said, for the amount of Rs. 33 crores, we should have a break-up—how much has been created to help the J & K complex, Modi business houses, Vimal Art Silk barons of Gujarat, Bakhia, Yusuf Patel and their tribe; and how much for the common man.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have said that before. The hon. Minister has taken note of it.

SHRI SEZHIYAN: George Bernard Shaw once remarked and I quote:

'A rich man gets ice in summer and a poor man gets ice in winter.' Here, in the same way, in the Finance Minister's attention, the poor man gets it at the time of imposition of taxes; and the rich man gets some attention, at the time of announcement of concessions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a topsy-turvy world in which we are.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है और जो इसमें कर्गों की छूट दी है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। 1952 से मैं देख रहा हूँ कि हर साल बजट पेश होता है, इसी तरह से चर्चा होती है और फिर बजट पास हो जाता है। ऐसा मैं कुछ नहीं देखता हूँ और काम चलता है। मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि राष्ट्र-पति के अभिभाषण के सम्बन्ध में थोड़ी बातें कही जाती हैं और फिर वही बातें जनरल बजट डिस्काशन पर और फाइनल विवरण पर भी उतार दी जाती हैं। मैं चाहूँगा कि मदन का काम समय लगे और सरकार का खर्चा कम हो इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार सोचे कि बजट के सम्बन्ध में वह कौन सी कार्यवाही करे।

दूसरी बात यह है कि जो पार्लमेंटरी सिस्टम है इसमें थोड़े से मिनिस्टर अधिकारी होते हैं और उनके नाँचे व्यूरोक्रेट्स होते हैं। वही बजट बनाते हैं, चाहे मन्त्री या प्रधान मन्त्री के विश्वास से लेकिन मदन में ऐसा मालूम होता है कि उसको छिपाकर रखते हैं और पांच बज के बाद बजट के ऊपर भाषण होता है। बजट के दो हिस्से होते हैं—एक 'क' और दूसरा 'ख'। भाग 'क' जनरल सर्वे के संबंध में होता है और भाग 'ख' में असल बात होती है कि कहां-कहां पर टैक्स लगाना है। तो मैं यह चाहूँगा कि जिस प्रकार से आर्थिक समीक्षा पेश करते हैं वैसे ही 'क' को भी उसमें लगा दें तो बाकी भाग 'ख' में कम समय लगेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इस हाउस में इतने सदस्य हैं, हम साल में 6 महीने यहां बैठते हैं और तमाम विधायक पास करने हैं, लेकिन हमारा क्या पार्टिसिपेशन है। आज जो सोशलिस्ट कन्ग्रेस हैं वरु पार्लियामेंटरी सिस्टम के खिलाफ हैं। वह कहते हैं कि साल भर जो बकबक करते हैं उमम काम क्या होता है।

इस उम्र में पहुंचने के बाद मैं गहमूस करता हूँ कि पार्लियामेंट का सदस्य होने के नाम मैं जनता का कौनसा काम कर रहा हूँ। मैं न ३० खुदवा सकता हूँ, न नहर निकलवा सकता हूँ, न बिजली दिलवा सकता हूँ और न स्कूल बनवा सकता हूँ। तो मैं कौन सा काम कर सका हूँ। तो यहाँ आज बड़ी मुश्किल से चास मिला है कि मैं अपनी बात कहूँ। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बड़े मंत्री जी नहीं हैं, उन के छोटे मंत्री हैं, वह मेरी बात उन तक पहुंचा दें कि सरकार जो आर्थिक समीक्षा देती है, उसका क' भाग तीन महीने पहले उपास्थान कर दें और फिर समस्याओं में पूछें कि कौन से टैक्स लगाने चाहते हैं और सरकार को आर्थिक परिसिद्धि मिले। मैं प्रो' क्या बरा काम करने चाहिए। कुछ इस तरह की बातें सरकार हम लोगों से पूछें। लेकिन हम लोग कौन हैं सिवाय इस के कि पार्टी से बंध हुए हैं। पार्टी कहें "हां", तो हम ने भी 'हां' कह दी और अगर 'ना' कहे, तो हम ने भी 'ना' कह दी और अगर विरोधी पक्ष अच्छी बात कहे और अच्छा नियम बताए, तो कहेंगे कि खराब है। इसलिए हम तो इस बात के लिए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जैसी दुनिया की परिस्थिति हो गई है, उस के बारे में हमारी सरकार सोचे और हमारे पार्लियामेंट्री एफेयर्स के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वे भी सोचें कि यह तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही है, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहां तक सुधार लाएं और कौन सा सुधार लाएं जिस से सब का पार्टिसिपेशन हो। थोड़े से लोग मंत्री हो जाते हैं और दूसरी तरफ व्योरोक्रेट्स हैं। हमारी कांस्टीट्यूटिवी का कोई माला है या कोई विकर्त हैं, जिन

का सेंट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्ध है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मंत्री जी से अगर कुछ कहेंगे, तो मंत्री जी व्योरोक्रेट्स से पूछेंगे। वे हमारी बात के आदमी हैं, हमारी समाज के आदमी हैं और शायद दे कर मंत्री बन गये लेकिन वे व्योरोक्रेट की बात मान लेते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं। हमें जनता चुन कर भेजता है, दस लाख जनता चुन कर भेजती है लेकिन हमारा क्या अधिकार है डेमोक्रेसी में। इसलिए इस समय आ गया है कि सरकार इस बात को सोचे। हम को डेमोक्रेसी चलाना है। डेमोक्रेसी में जा मेम्बर है और उस की कांस्टीट्यूटिवी की जो समस्या है और जो समस्या सीधे केंद्रीय सरकार से सम्बन्ध रखती है, उस का कैसे हल करें। किन्तु क्षेत्र में विरोधी पार्टी का मेम्बर आया या कांग्रेस पार्टी का आदमी आया, तो वहाँ की समस्या हल होनी चाहिए। हो सकता है कि पहले एक आदमी आया और उसके बाद दूसरी पार्टी का आदमी आया लेकिन जनता की सेवा होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि केंद्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया है। रूरल इजीनियोरिंग के लिए दिया, बिजली के लिए दिया, नहरों के लिए दिया, बाढ़ नियन्त्रण के लिए दिया। हम लोग लोक सभा के सदस्य हैं और हम डाइरेक्ट जनता से चुन कर आते हैं लेकिन इस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य सभा में स्टेट के रेप्रेजेंटेटिव है लेकिन हम तो सीधे जनता के रेप्रेजेंटेटिव हैं पर अपने क्षेत्र में इन चीजों के बारे में जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट का पैसा देती है, उस पर हमारा क्या नियन्त्रण है? व्योरोक्रेट उस को खर्च करता है और स्टेट गवर्नमेंट से आप पूछते हैं तो वह जिस तरह से चाहे आप को जवाब दे देती है। हम आप के पीछे न रहें, आगे से अधिक आप के पीछे न रहें, तो एक दिन सरकार नहीं रह सकती है। हम आप के पीछे पीछे चलते हैं अपनी सरकार को कायम रखने के लिए

और हमारी बात कोई पूछता ही नहीं है और न हमारी बात को माना जाता है।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : किसी एम०पी० की बात नहीं मानी जाती।

श्री विभूति मिश्र : आप सुनिये। दूसरी बात यह है कि आप इंग्लैन्ड का तरीका देखिये। इंग्लैन्ड के बारे में आप ने पढ़ा होगा कि वहां पर क्या होता है। वहां पर यह तय कर लिया जाता है कि विरोधी पार्टी के कौन-कौन से लोग बोलेंगे, उन के बेक-बेन्चर्स में से कौन बोलेंगे और सरकारी पक्ष से कौन बोलेंगे और उन के बेक-बेन्चर्स में से कौन बोलेंगे और सरकारी पार्टी के जो मिनिस्टर होते हैं वे रोज ब रोज अपनी पार्टी के मेम्बर्स से मिलते हैं और उन की समस्याओं के बारे में पूछते हैं और उन से बात करते हैं लेकिन हमारे यहां क्या हालत है। कुछ थोड़े से मिनिस्टर्स को छोड़ कर हम मेम्बर्स की बात जहां भी हम जाने हैं मुनी नहीं जाती है। मैं तो अब ऐसा समझता हूँ कि मेरी आस्था डेमोक्रेसी से खत्म सी हो रही है। यह जरूर है कि आप ने विस्फोट किया, आप ने स्पेस में स्पुटनिक को घुमाया। यह आप ने बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन जो मौलिक बात है, उस को आप सोचिये कि मासेज और मासेज के रेप्रेजेंटेटिव्स का पार्टीसिपेशन डेमोक्रेसी में हो। आज जनता चाहती है कि सभी का पार्टीसिपेशन हो। हमारा क्या कन्ट्रिव्यूशन है, हमारा क्या पार्टीसिपेशन है, सिवाय इस के कि रघुरमैया जी ने 'हां' कह दिया, तो हम ने भी 'हां' कह दिया और 'ना' कह दिया तो हम ने भी 'ना' कह दिया। इस के सिवाय सरकार में मेरा क्या अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मन्त्री जी इस बात पर सोचे और विचार करें और प्रधान मन्त्री जी से भी राय लें। मैं चाहता हूँ कि इस पर वे गम्भीरता से सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्राइस कमीशन बना दिया गया। कभी यह सरकार को इस चीज को नहीं लाती है कि गेहूँ का दाम जो

105 रुपया फिक्स किया है, तो गेहूँ को पैदा करने में किसान की कितनी लागत आई होगी। उस का डेटा क्या है, क्या चीज है, यह सदन के सामने आज तक नहीं लाया गया और हमारे सामने यह नहीं आया। उसी तरह से कपड़ा आप हम को देते हैं, तेल देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं, सब का उत्पादन खर्च सामने आना चाहिए लेकिन वह आता नहीं है और एड हाक बेसिस पर कीमत फिक्स कर देते हैं। प्राइस कमीशन में जो लोग हैं वे किसान के रेप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। उन्होंने जो एड-हाक बेसिस पर प्राइस फिक्स कर दी, उसी को सरकार मान लेती हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि आप की पार्टी के आदमी हैं और आप के टिकट पर आए हैं।

मुझे आप 15 मिनट दीजिए। मैं इस सारे बजट सेशन में किसी चीज पर नहीं बोला। इसलिए प्राइस कमीशन के सम्बन्ध में आप को असली बात को देखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि 24 साल देखने के बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ने कौन सी ऐसी स्कीम बनाई है यंगमैन के लिए। उन को आप कैसा बनाना चाहते हैं। आप नेशनल पर्सनेलिटी को बर्बाद कर रहे हैं। कौन सी एजुकेशन की आप ने स्कीम बनाई जो कि जोब-आरियेनटेड हो। आप यह बजट लाते हैं तो इस बजट में कुछ ऐसा रखिये कि हिन्दुस्तान ने जो नौजवान है जिस को कल हिन्दुस्तान का चार्ज लेना है, वह कैसा आदमी हो या किस प्रकार का आदमी हो। यों तो आप जवाब दे दीजिएगा और हम 'हां' कह देंगे, लेकिन आप को इस के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा क्या पार्टीसिपेशन है। इसलिए एजुकेशन के सम्बन्ध में और जो हमारे नौजवान हैं, इन के सम्बन्ध में आप कुछ सोचिये और कुछ काम कीजिए।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। चीनी मिल वाले कहते हैं

कि हम को चीनी जो है वह ज्यादा खर्चीली पड़ रही है और उन को ठीक पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों का जो पैसा बाकी है, इस के सम्बन्ध में कुछ सोचिये और मिल वालों से कुछ बात कीजिए कि क्या बात है, क्या कठिनाई है और किसानों को पैसा क्यों नहीं मिलता है।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि जूट इण्डस्ट्री बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में खत्म हो रही है। आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि 68 लाख बेलों की जगह 48 लाख बेल हो रहे हैं। जूट इण्डस्ट्री किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहीं जाती थी और अब जूट इण्डस्ट्री खत्म हो रही है। इस के बारे में आप कुछ सोचिये।

मेरे यहां गण्डक प्रोजेक्ट है। इस पर एक अरब 30 करोड़ रुपया खर्च हो गया और इस से दो लाख एकड़ भूमि में पानी मिलता है जबकि आन्दजा था कि 30 लाख एकड़ में पानी मिलेगा। इतना रुपया आपने समाज का इस में लगा दिया और इन्प्लेशन कर दिया। यह जो इन्प्लेशन है, इस के जवाबदह आप हैं। जब आप ने इस स्कीम को लिया था, तो आप को चाहिए था कि जल्द से जल्द यह स्कीम पूरी हो जाए और इस से उत्पादन हो। आप इस का जवाब नहीं देते हैं और कहते हैं कि इन्प्लेशन है, इन्प्लेशन है। इस इन्प्लेशन के आप जवाबदह हैं। जब आप ने इस स्कीम को लिया था, तो आप को इस को पूरा करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। उस में सीपेज का बखेड़ा है और भी कितनी दूसरी दिक्कतें हैं। उस स्कीम को आप पूरा करें।

14 hrs.

सारे देश में पर कैपिटा इनकम बिहार में कम है। जब आप बजट बनाते हैं तो आपको देखना चाहिये कि कहां कमजोरी है

इस स्टेट में और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उस स्टेट को आप कोई ज्यादा अनुदान या सहायता दें ताकि वह आगे बढ़ सके, पर कैपिटा इनकम उसकी बढ़ सके। नागालैण्ड और मिजोराम का हमारे बाद हो नम्बर आता है। आप कोई स्कीम बनाइए या बजट लाइये इस तरह की कमियों को दूर करने वाला, उसको सब के सामने रखिये और बताइये कि फलां फलां स्टेट के लिए आप यह करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ आप करते नहीं हैं।

बिहार में इलैक्ट्रिसिटी की भी बड़ी कमी है। वहां सिंचाई का काम भी इसकी कमी की वजह से नहीं हो पाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और सेंटर पैसा नहीं देता है और सेंटर को जब एप्रोच किया जाता है तो वह कहता है कि हमारे पास पैसा है ही नहीं। किसी स्टेट को तो आपने ज्यादा धनी बना दिया है और किसी स्टेट को कमजोर। यह शुभ चिन्ह नहीं है। इस और आप ध्यान दें।

वियतनाम आजाद हो गया है। कम्बोडिया हो गया है। चीन को ही आप देखें। वहां आमदनियों में एक और पांच का फर्क है। यहां पर जो डिसपैरिटीज हैं उनको भी आप दूर करे। लेकिन यहां तो यह बढ़ती जा रही है। क्लास 1 और क्लास दो के जो अफसर हैं उनके घरों को जा कर आप देख लें, जो धनी लोग हैं उनके रहन सहन को आप देख लें और गांव में जो गरीब है उसको आप देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा। यह जो हालत है इसको सुधारने के लिए आप कोई ऐसा कदम उठाएं ताकि यह जरे फर्क है यह दूर हो, कम हो। एक और पांच नहीं कर सकते हैं तो एक और दस ही आप कर दें। कोई डाइनामिक काम करने की जरूरत है। डिनामिक काम आप नहीं कर रहे हैं।

हमारे विरोधी लोग युनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दिन ये युनाइट हो गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी सरकार से कहता हूँ कि मेरी सरकार कोई ऐसा कदम उठाए ताकि विरोधी दलों की दाल न गलने पाए, आप आगे बढ़ें, जनता की सेवा करें और ऐसे कदम उठाएं जिन से जनता को लाभ है, उसकी जो तकलीफें हैं, उनको दूर करें। मन्त्री लोगों का जो रहन सहन है यह बिल्कुल सादा होना चाहिये। जवाबदेही के जो काम हैं उनको आप गरिमा के साथ पूर्ण त्याग और तपस्या के साथ पूरा करें ताकि जनता में हमारी पापुलेरिटी बनी रह सके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनता में हम पापुलर नहीं रह पाएंगे। आप साबित करें कि आप गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं। जिस तरह पुत्राल पर वह सोते थे, राजेन्द्र बाबू सोते थे वैसे ही आप भी सोएं। जगजीवन राम जी मेरे यहां आए थे और जिस तरह से मैं पुत्राल पर सोता हूँ उसी तरह से वह भी पुत्राल पर सोए थे। बजट के मामले में आप सभी मੈम्बर्स को कॉन्फिडेंस में ले और ले कर आवश्यक कदम उठाएं ताकि देश का क्याण हा।

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first and foremost, I would like to congratulate the hon. Finance Minister and Mr. Mukherjee, Minister of State for Finance opposite, for a very practical Budget that they have presented to the country this time. I would also like to congratulate them on the reliefs that have recently been announced in which the poor man would, to some extent, benefit. What makes me happy is that, for the first time, I would say after a very very long time, a Budget has been presented with very little prejudices behind it.

I shall, today, confine my speech mainly to avoidable public harassment. Knowing fully well the fair attitude of the Finance Minister and

the Minister of State opposite, I would like to place before them today certain suggestions and I think, with their interference, they might be able to remove these harassments and impediments in the way of honest taxpayers and honest citizens.

First and foremost, I would like to say a few things about the famine that is prevailing in some parts of Rajasthan. As you are no doubt aware, with all this talk of socialism, the villager expects that he should at least have the benefit of famine relief near his vilalge within a distance of ten miles, as used to happen for the last 30 years. Now, if you go into the villages, you will find that no famine relief is given to the people at all within 10 miles of their homes. Every body is asked to go almost upto 300 miles and collect on the Rajasthan Canal where famine work is provided. I am not opposed to the idea of labour being shifted to the Rajasthan Canal, provided you have facilities for housing them and looking after them. I had occasion to visit some of these camps last January and this month. People in sub-freezing conditions were asked to lie down in the open, and even *sirkis* for building their little huts were not provided in time.

Another thing is that according to the Famine Code, every village must have access to a famine relief camp within ten miles. in the name of socialism, I would appeal to the Government kindly to see that the State Government takes steps in this direction.

Another thing is that the Rajasthan Canal, which is one of the mightiest canals in the world, has two prongs. the main canal and the lift channel. Now on the main canal, the famine labour which is working there is being paid 25 per cent per day more than they are paid on the lift channel. I think this is entirely unfair and I would like to draw the hon. Minister's attention to it.

The next point is about pipe lines in the desert. In Israel and in many

[Dr. Karni Singh]

other parts of the world where they have drinking water problems, it has been possible for long pipelines to connect vilages for drinking water purposes. Now in the desert, the Rajasthan Canal is coming through some of the most inhospitable parts of the world where drinking water cannot be provided locally because it is brackish and is not fit for human consumption. It is entirely possible to connect villages upto 50 miles from the main Canal and lift channel and give them drinking water all over so that there will hardly be any part of the desert without availability of drink water.

The next thing I would like to suggest is that in the Churu district of Rajasthan, where drinking water problems are very acute, there should be some way of getting water from the lift channel.

The next point concerns an avoidable harassment. This relates to the question of people living in the Lunakansar area where the lift channel is coming. In the Gram panchayat of Kokharan, Government have decided to set up an artillery range. Now, we cannot dispute the needs of the defence services. This range is unfortunately being situated right in the middle of the irrigation project, i.e. the land lying between the main canal and the lift channel. What is more, they have asked the vilages to evacuate. Twelve vilages are totally being evacuated and 20 vilages are being partially evacuated. The people of these 20 vilages are asking that they should be totally evacuated if evacuation is necessary and rehabilitated in the Canal areas and proper compensation paid. I think that is a fair request. I would request the hon. Minister to be kind enough to look into the matter.

Coming to harassment to the taxpayer, I have spoken many times on the Finance Bill on different aspects of it, but today I would only concentrate on what I consider to be avoidable harassments. Here again, I am

speaking only for the honest citizen. I have nothing to say for the dishonest man. Every decent citizen of this country wants to pay his tax because it is his duty as a citizen to see that funds are available for development. But the Indian taxation system has become so entirely complicated that even the hon. Minister opposite may not be able to answer any particular question put to him right-way and every lawyer has some different interpretation of the law. As a result, the tax payer is in a total quandary.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not very wrong.

DR. KARNI SINGH: So I bring this to the attention of the hon. Minister.

First and foremost, I would make a suggestion, that in view of the highly complicated nature of the taxation structure in India, which even the government officers in the Finance Ministry find difficult to interpret without reading at least a dozen books, Government should create a special cell in the income-tax department which may be called the "Guidance Cell" which the taxpayer could approach for free advice and interpretation of any tax law applicable to him. Any advice tendered in writing by this Cell would then be a protection for the citizen and binding on the tax department. In a socialist country, I am sure Government do not wish the citizens to waste their time going from one lawyer to another, but rather spend their time for productive work in the service of the country.

As regards equitable distribution of wealth there can be no two opinions I stand for having said in this very House for half a dozen years or more, if there is inequitable distribution, bring in a capital levy, fix a limit that a citizen should have and take the rest. But I think it is totally unfair that any citizen should be asked to pay more in direct taxes than his total income because that compels a man to become dishonest. It is unfair that any man should be punished to a

corner where he must resort to dishonesty. Millions are paid by the tax-payer. Yet the sad part is that if you are to visit the villagers in our country and the desert areas in our country, where I can speak with some authority, for constructing wells or buildings, schools and hospitals even for these public amenities a villager who has not got a shirt on his back is asked to pay a contribution. Why are we paying our taxes then? If we pay our taxes, the least the Government can do is to build schools, hospitals, wells and roads for the people. It is an entirely unfair attitude that the people should contribute in everything and yet pay exorbitant taxes.

I should like to suggest a few things to the hon. Minister for his kind consideration, things which I once again call avoidable harassment. Under the direct taxes laws in India, there is no time limit prescribed for completion of wealth and gift tax assessments. In most of the cases assessments are pending for more than ten years. At the time of filing of returns the assessee has resources for paying the tax but when his assessments are made after a period of ten or more years, and that also at a much higher figure than that returned by him he may not be in a position to pay the tax at all. I had brought this to the attention of the hon. Minister Shri Subramaniam earlier and I say this once again that the assessments must be completed soon. You cannot have assessments pending for ten years.

Another thing is harassment by income-tax officers. By and large the income-tax officers in our country are honest and fair-minded but temptations that are offered by Government to the income-tax officer for his promotion—it may not be in writing—create difficulties. For his promotion, the income-tax officer may have to depend upon how much money he squeezes from the citizen and this results in his giving all kinds of unfair demands, knowing that the higher appellate authorities will then correct it and do justice. Under the direct-tax laws, there is no time limit prescribed for disposal of appeal or recti-

fication applications and the assessee has to pay interest on demands till the date of the appellate order. Why should the citizen be penalised for payment of interest for delay by the department in disposal of appeals or rectification applications? Although there are no written rules, it is well known that promotions of ITOs are based on the amount of taxes they collect. This can after result in harassment of the citizen. I think the hon. Minister knows it better than I do that the income-tax officers do have these orders. The idea behind it is certainly not to harass the people but it results in harassment. I sincerely hope that the hon. Minister will look into the matter.

The third suggestion is about the delay in payment of refunds. As per the taxation laws, an honest citizen has to pay interest and penalty for late payment of demands against him but there is no remedy for him for recovering the refunds due to him as the department is at liberty to take as long a time as they want, firstly for making the adjustment for working out refunds due and secondly for payment of refunds. In most of the cases, the citizens are harassed by the department by adjusting their refunds due against the demands raised by the ITOs by making wrong assessments.

Under the new penal laws, the Government has provided government approved valuers for property, jewellery, etc. whose valuation is supposed to be authoritative. If this be the case, the department should accept the valuation reports of those valuers while in most of the cases the department enhances the value stating that the amount of the valuation reports is undervalued. Why should a citizen be liable to pay more taxes on those enhanced valuations when he has got the valuation done from the government approved valuers? If the valuation by the approved valuer appears faulty, the department should cancel the licence of the valuer instead of harassing the citizen to pay more tax. In such cases the department should

[Dr. Karni Singh.]

withdraw the licence and give it to those persons who are more trustworthy and accurate.

I should like to request the hon. Minister let us also in India have a taxation system whereby a man goes to the tax department picks up a form and files in his tax return and attaches his cheque and for the rest of the year he can spend his time for serving his country. In our country today the tax-payer is tied up in a noose; he is something like a fly in the spider's web. And he can never get out of it because there is no way of getting out of it and I am sure Shri Subramaniam and Shri Mukherjee would realise the situation and being practical men, I sincerely hope that they could find some way out whereby a tax payer, whether he is a small tax-payer or a big tax-payer, be able to utilise his time more profitably in the interest of the country by simplification of the taxation structure.

Now, Sir, there is one more point which I would like to highlight in the House today and that is about the harassment caused to the millions of citizens by duplicate charge of telephone bills. I have my own experience and my friends also tell me about this. Now, in our country—I do not know whether you are probably the victim as I am—telephone bills for four or five years keep on coming up suddenly and we do not know what to do to find out if it has already been paid or not. I have tried to tell the Minister who is in charge of Communications that no bills in the Telephone Department should be pending for a period of over one year and any bill that has been pending for over a year should automatically be terminated and written off.

Secondly, any house-wife or any telephone subscriber in this country should have a right to approach the Telephone Department concerned and say 'please give me in writing after I settle this bill that there are no further bills pending against me'. At

least the house-wife will be free then from this worry of earlier bills. I can tell you from my experience that after the suggestion I got a bill of 1973 recently after having received from the Department that "there were no bills pending on any parliamentary telephone." Now, if this is happening to a Member of Parliament, what happens to the millions of people who are not M.Ps? So, the Government has to do something seriously about this problem of telephone subscribers bill.

Now, I give you another example. In Bombay, I have a telephone on which I received a duplicate bill for about Rs. 4000 I complained to the Government and I even wrote to the Minister. They said: "No. The bill was correct". Finally they found out that they charged Rs. 4,000 twice over but they insisted that I make the payment and so I paid it. It was later refunded. Now, the other day on my parliamentary telephone in Delhi, I found that an amount of about Rs. 3,000 was doubly charged and was refunded after much correspondence. Now, these harassments are happening every day to the people in our country and the Members of Parliament are trying to bring this point to the notice of the Government. I agree with my hon. Member Shri Bibhuti Mishra who was very right in what he has stated just now that the Members of Parliament are virtually becoming ineffective and useless. And I can say from my own experience that when we go to our villages or to our cities, and talk to the people, they are misunderstanding us; they ask us "what have you done for we voted for you; you are doing nothing in Delhi for us". We M.Ps feel frustrated because we realise the people's problem only too well but Government must be more receptive to the needs of the people and the suggestions of M.Ps. The question is, what are we doing here? Surely we are not coming here merely to receive fifty rupees a day. We are the representative of the sovereign

Parliament. Our job is to place before this sovereign legislature the needs of the people we represent and I think Shri Bibhuti Mishra has done a great service to our country by highlighting this point. He is a senior Member and the Government should pay more attention to this problem.

My last point is about sports. We have been very lucky that we won the World Cup hockey match. I have had the honour to wear the colours of my country and to carry the flag many many times and I am very proud of our hockey players and very proud of all our sports men. But let me tell you one thing. I want this to be on record in the Lok Sabha that winning the hockey in Kuala Lumpur does not mean winning the hockey in Montreal. There are other countries like China which are trying to outwit us. They and other Western Countries are not prepared to accept a dark raced country like us to take the gold medal in hockey. But we want to show them that not only in hockey can we win but we can win in shooting, wrestling, tennis and in other sports also. And to achieve that it is absolutely imperative that the planning for the Olympics takes place from now itself.

Now, I will give you just a small example. It will make this House laugh and that is about the shooting sport of which I know something. The team was selected to go to Munich Olympics in 1972. Now the Munich Olympics was about three years ago. One and a half years before that I went and saw the Education Minister and presented to him the needs of the shooting team. Nothing happened and the cartridges that had finally and belatedly got ordered when the team was going to Munich, arrived one year after the Olympics were over. Finally when last year it was decided that the shooting team could go to take part in the Teheran games, we asked them for cartridges because the new international rules barred the previous ones

ordered for Munich. These cartridges are still not being cleared from customs and Teheran Games were over nine months ago! If you want that the Indian team should do well in the Asian Games or World Meets or Olympics please bear one thing in mind: There are countries today in Asia like China who are already training their sportsmen so hard that the time will come when they will not allow a country like India to win and that would hurt our national pride. Please bear in mind that you should plan for the training of your sportsmen at least two years in advance of a major event.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गेंदा सिंह, सिर्फ

10 मिनट ।

श्री गेंदा सिंह (पदरोना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ कभी-कभी कुछ ज्यादाती हो जाती है। मुझे जब यह कह दिया जाता है कि तुम इतनी देर में ही अपनी बात खत्म करो, तो मुझे बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा इस सम्बन्ध में सोचना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक दिन मैं खड़ा हो गया और अखबार वालों ने लिखा कि अपवाद स्वरूप यह खड़े हुए और इनको बोलने दिया गया। उस दिन के बाद अध्यक्ष महोदय कुछ नाराज़ हो गये मेरे ऊपर। मैं कहना तो उनके सामने चाहता था, लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि कुछ मुझ से बेवकूफी हो गई, तो क्या आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे? वह ऐसा काम था, जिस पर मुझे खड़ा हो जाना पड़ा।

दो-तीन बातों को तरफ़ में आपका ध्यान इस वक्त दिलाना चाहता हूँ। पहले तो मैं श्री सुब्रह्मण्यम् और श्री प्रणव कुमार मुखर्जी को धन्यवाद दूंगा और खुशो जाहिर करूँगा कि उन्होंने खण्डसारी बालों पर मेहरबानी की। इतना वह जरूर ध्यान रखें कि उन्होंने मेहरबानी तो की, जिससे भविष्य

[श्री गेंदा सिंह]

में भला होगा, लेकिन इस वक्त गन्ना किसानों पर ज्यादाती हो गई। उनका गन्ना बहुत देर तक खड़ा रह गया। यह एक अंधेरे में काम चला दिया गया, उसमें नुकसान किसानों का हो गया। मन्त्री महोदय कोशिश करें कि किसानों का नुकसान न हो सके और उनको बचाया जाये।

भागवत कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ विचार हुआ। कुछ इने-गिने लोगों को छोड़ कर पूरे हाउस का मत था कि कमीशन के आधे मेम्बरों की रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिये और गन्ने की फ्रैक्टरियों को नेशनलाइज करना चाहिये। सन् 1951 के बाद देश के अन्य भागों में जितनी फ्रैक्टरियां बनी, वे करीब करीब सब को-ऑपरेटिव सैक्टर में बनीं। किन्तु नैवटिया, बिरला, बिसारिया, कनोरिया, थापर आदि हिन्दुस्तान के जितने भी पूंजीपति हैं, वे सब यू० पी० और बिहार में बैठे हुए हैं। वे ऐसी जगह बैठे हुए हैं, जो बहुत बैकवर्ड इलाका है, जहां किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने 30 वर्ष में इतना धन कमाया है कि वहां वे राजा हो गये। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में दो हिस्से मत बनाईये।

आज यू० पी० और बिहार की क्या स्थिति है? श्री विभूति मिश्र इस समय सदन में नहीं हैं। श्री भोला राजत बैठे हुए हैं। इकनामिक दृष्टि से यू० पी० और बिहार पूरे देश में 15वें और 16वें नम्बर पर हैं। इतने बड़े प्रदेश होने के बावजूद, इन दोनों प्रदेशों की आज जो दुर्गति है, उस पर अजर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो जैसे मुझे लकवा मार गया है, वैसे ही इस देश को भी लकवा मार जायेगा।

यू० पी० और बिहार आज पूरे देश में 15वें और 16वें नम्बर पर क्यों हैं? इसलिये कि वहां नैवटिया और बिस्लत आदि ही अरे

पड़े हैं। इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

1969 में जो कमीशन बना, उसके आधे सदस्यों की रिपोर्ट पर इस सदन में विचार नहीं किया गया। इतने दिनों तक सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकी है; अब उसको इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये। श्री मुकर्जी नौजवान आदमी हैं, श्री सुब्रह्मण्यम्...

एक माननीय सदस्य : बूढ़े हैं।

श्री गेंदा सिंह : ...समझदार आदमी है। वे बूढ़े हैं, तब भी वे काम करने वाले आदमी हैं।

मेरा अनुरोध है कि वह इसका कुछ उपाय करे और यू० पी० तथा बिहार के लोगों का उद्धार करे।

जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, कंट्रोल्ड कपड़ा, टैक्सटाइल कमिश्नर, और टैक्सटाइल कमेटी, ये सब चीजें इतने बड़े की हैं कि मेरी समझ में नहीं आती है। कंट्रोल्ड कपड़ा गरीब आदमी को मिलना चाहिये, लेकिन क्या वह उनको मिल पाता है? मिलों को 24, 25 परसेंट कपड़ा बनाना चाहिये। प्राइवेट मिले कंट्रोल्ड कपड़ा नहीं बनाती हैं, दयाबाजी करती हैं। उन मिलों पर सरकार का पूरा कब्जा होना चाहिये। जब तक ऐसा न हो, तब तक सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि रुई पैदा करने वाले मुसीबत में न पड़े और कपड़ा खरीदने वाले गरीब आदमी भी मुसीबत में न पड़े।

सरकार के हाथ में जो 105 मिलें हैं, उनके द्वारा कंट्रोल्ड कपड़ा बनवा कर लोगों को दिया जा सकता है। जो दूसरे कारखाने हैं, उनसे भी कंट्रोल्ड कपड़ा बनवा कर सरकार अपनी मशीनरी के द्वारा लोगों को दे सकती है। श्री मुकर्जी अपनी मशीनरी को ठीक करें। मुझे उस मशीनरी में बहुत गड़बड़ मालूम हुई है।

बम्बई में 8, 10 रोज रह कर मैंने टैक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय के मामलों को जानने की कोशिश की। हमारे मिनिस्टर नौजवान लोग हैं। इन नौजवान लोगों से काम लेना चाहिये। यहां दिल्ली में बैठ कर या केवल हवाईजहाज पर उड़ने से काम नहीं होगा। अगर वह जमीन पर रहेंगे तो सरकारी मशीनरी उनके रुआब में आयेगी और उनकी बात सुनेगी। हवाई जहाज पर उड़ने की बात गरीब आदमियों की समझ में नहीं आती है।

तीसरी बात एक और कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसका रिश्ता बड़ा बना है। इसी का है शायद रिजर्व बैंक। इसको क्रेडिट न देने का, क्रेडिट कंट्रोल करने का अख्तियार है। बहुत अच्छा है। लेकिन कहां करते हैं ये कंट्रोल? कंट्रोल करते हैं कि गन्ना के किसान को दाम नहीं देने देंगे। रूई के दाम को नहीं देने देंगे, जूट के किसान को दाम नहीं देने देंगे। प्रणव जी जरा सोचें इस चीज को। बहुत कुछ कंट्रोल किया, मुनाफे को कंट्रोल किया, डिबिटेंड को मना किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन गन्ने का किसान, काटन का किसान, जूट का किसान आज बैठा बैठा रो रहा है। अरबों रुपये उसके बकाया पड़े हुए हैं। आप बकाया देने को मनाही नहीं करते हों। लेकिन बकाया उसको मिल कहां पाता है? आप क्यों नहीं ऐसा इंतजाम करते कि रिजर्व बैंक से जिस बक्त वह पैसा लें वह पैसा सीधा किसानों के घर जाय। ऐसा कुछ हुआ था पहले। लेकिन नहीं हो सका यह। सुनहूप्यम् साहब एग््री-कल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं प्रणव जी से भी कहना चाहता हूं। इंदिरा जी को बार बार हर मामले में पकड़ना नहीं चाहता, यह काम आप लोगों को करना है, नौजवान लोग जो मिनिस्टर बैठे हैं उनका काम है यह कि इस तरह की बातों को ठीक रास्ते पर ले आएं। अगर वह सब्त रहेंगे तो यह काम हो सकता है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि रिजर्व बैंक को जरा अकल सिखाएं कि रिजर्व

बैंक अगर क्रेडिट कंट्रोल करना चाहता है तो उससे किसान न मरने पाए। वह खाद इस साल नहीं ले सका, उसका गेहूं ठीक नहीं हो सका।

SHRI VIRENDRA AGARWAL (Moradabad): The Finance Minister has painted a rather rosy picture of economic outlook for 1975. The marginal tax concessions totalling Rs. 33 crores have been widely appreciated. It is true that the decline in prices of nearly 7 per cent in the last 7 months has created a good economic climate, but it is equally true that the Government has entirely concentrated on curbing the demand and credit in the legitimate economy. The Government is still not in a mood to tackle political corruption or to curb the parallel economy and sweep away the regime of price controls, high excise duties and special rates of direct taxation which had given birth to the parallel economy. As a result, the flow of funds into the black economy continues to remain unchecked. If the Government really wishes to ensure the economy against a further bout of inflation, the right course of action for it will be to reduce the floating cash at the disposal of the parallel economy and increase judiciously the credit and other facilities needed by the legitimate economy to finance a higher level of production.

We as a nation are groping in the dark, while the economy continues to remain in the doldrums. The Finance Bill of 1975-76 lacks Government's response to the unmistakable signs of a deteriorating state of affairs, though the Government always claims to be committed to growth and stability and also to eradicate poverty and inequality. The Finance Minister had an excellent opportunity to introduce certain fiscal measures which could have revived the economy in the pre-election year, but he has missed the bus. The current wave of political unrest in the country stems from the fact that prolonged economic stagnation, mounting shortages, inflation

[Shri Virendra Agarwal]

and growing unemployment have greatly widened the gap between the privileges enjoyed by a small segment of the society and the burdens borne by the masses of the people. The investment famine which began in 1966 and the shortages to which it has given rise have greatly accelerated the divorces of power from accountability in the economic sphere. It has heightened inflationary pressures and brought about a sharp fall in the real incomes of the vast majority of the people. It has given a tremendous boost to the black market and greatly increased tax evasion particularly by the self-employed and the owners of the small-scale enterprises. The net result is a rapid transfer of incomes from the poor to the rich, and more specifically from the wage and salary earners to the self-employed.

It is widely recognised that the panacea for all our economic ailments lies in fiscal reforms. If the price stability is to be made a permanent feature of the economy and growth is to be accelerated at a faster pace and economic Swaraj made a reality, then rationalisation of the tax structures can no longer be postponed. The constant raising of tax rates year after year has reached the situation point while they inhibit generation of further wealth, attract the law of diminishing returns which implies lower revenues to the exchequer and creation of black economy. None of the national objectives can ever be achieved if this policy is not immediately reversed. On the one hand we have to accelerate the pace of growth and on the other we have to create demand, implying more purchasing capacity in the hands of the people. The U.S. Government has recently announced a tax cut amounting to 70 billion dollars which means that the tax collected from the people has been returned to the people so that they can buy more from the market, thus raising the purchasing capacity of the people.

What is required today is to cultivate a philosophy of growth which is

non-inflationary and will in fact counter inflation by balancing supply against demand rather than think of anti-inflationary measures which inhibit growth and make no appreciable difference to prices. This is precisely what has been happening in recent months during which anti-inflationary measures of doubtful effectiveness have been operating. The Government can certainly congratulate itself on a temporary phase of price stability, but we are doing at the cost of growth.

A higher growth rate is the most effective answer to meet the situation, but the crux of the matter is that under the system of heavy taxation there is little margin to save and even less inducement to earn. We all know that private investments are deflationary in character while public investments have always resulted in inflation. The combined effect of confiscatory tax rates, high prices and heavy excise duties leaves little scope for a surplus after meeting normal expenses and consequently there is no scope for investment from assessed incomes. Unless this scope is enlarged and suitable incentives are provided for investment in priority sectors, all talk of growth will have little meaning. Domestic saving which constitutes the largest single item in investment is not coming up to expectations. The steep rise in the price level as well as direct taxation has adversely affected it.

On the Reserve Bank's estimates, the computed savings in real terms have increased only by Rs. 329 crores in 1973-74, which is negligible. As regards capital formation again there was a significant decline in the corporate sector, gross capital formation being only 9 per cent as against 13.5 per cent in the preceding year. What do we need today? We know that the Government should immediately introduce some bold steps to encourage domestic and corporate

savings and induce savings and investment.

The Finance Minister should have taken courage to limit taxation to 50 per cent, upto Rs. 2 lakhs, and introduced a slab of Rs. 2 to 3 lakhs with a tax rate of 50 to 60 per cent and a rate of 70 per cent on slab above Rs. 3 lakhs.

This rationalisation of taxation should be linked with a scheme of compulsory savings and investment in priority industries. This is the only way to bring about not only industrial expansion but an entirely new climate of confidence in the country. We feel really disappointed year after year when we plead with the Finance Minister that he must do something to raise tax exemption limit to Rs. 10,000. The rupee value has been hopelessly corroded and eroded and we know that the value of the rupee is no more than 25 paise. The people in the lowest income group find it difficult to meet both ends. In such circumstances, I would lead with the Finance Minister again to think seriously and raise the tax exemption limit to Rs. 10,000. I think it is absolutely necessary when we talk so much terms of socialism, social justice, inequality and what not. Similarly, if we really want that the lower income group should participate effectively in democratisation of industrial structure, then we have to see that the smaller group could raise really the rate of saving, which is possible only when the tax exemption limit on dividend income is raised to Rs. 10,000.

I really see that so long as vital issues are not tackled properly, we can never revive economy. I really would like to plead with the Finance Minister to constitute a cell in the Finance Ministry which could advise the Finance Minister now and then on the question of tax measures, how it bring revenues to the exchequer, whether people are really capable enough to pay tax, and if they pay tax, to

extent, the exchequer really gets revenue. I feel, at the moment, this Ministry has no machinery, whatsoever, to advise the Finance Minister on such vital issues. We have seen here that the small sector, a small industry like *khandsari* and powerloom were subjected to very serious and hard taxation measures. I know that the Finance Minister always champions the cause of the farming community. I know that the Finance Minister stands for the labour community. What happens when he comes to the real task? I know while replying to the Budget debate, he did not favour granting remunerative price to the farmer or to give higher DA to Government Employees. I would like to deal with this particular question, because I certainly see that so long as we, as a nation, are not able to raise productivity, either in the farm or at the factory, we really cannot move further very fast.

Workers in organised industry have to fight for every increase in wages even those designed merely to offset the rise in cost of living and in the process have suffered a steady erosion of their real income.

Sir, we are happy that the Finance Minister, at the moment, is negotiating with the trade unions to evolve some sort of a uniform D.A. formula and also to talk in terms of wage structure. I feel that we have reached a situation when we must allow the working classes in this country to have a sense of belonging, a sense of participation in the national endeavours if they really want them to raise productivity.

As for the tenants, farmers and agro-labourers who actually till land and are therefore the most important segment of the country's working population, they have neither security of job nor security of tenure. Even this is not the whole story. The Government fixes absurdly low prices for their products. The nation's prosperity largely depends on

whether the workers and farmers are able to raise their living standards or not. If they continue to be neglected in a socialist State, it simply means that the Government is determined to betray them. Economy will constantly grow at a faster rate of the farmers and workers get higher income because that would certainly lead to higher productivity and higher G.N.P.

With these words, I would advocate for a national wage policy for all the employees, whether they are in Government, private or public sector, and also a realistic price policy for all agricultural products, including sugarcane, rice, wheat, jute and cotton. Further, I would like to go into two or three items individually. I must congratulate the Finance Minister for having introduced the compounded levy in the case of *khandsari* units. I think, he has really saved a cottage industry, a small-scale industry, from being liquidated. But the amount of levy he has put on *khandsari* now is too high. He has raised it by $2\frac{1}{2}$ times. I think, it is too much. If you see the figures, in 1960-61, the incidence of excise duties on per quintal of *khandsari* was only Rs. 1 50 p.; it was raised to Rs. 10 in 1973-74. According to your own original formula, it had gone to as high as Rs. 49. According to your latest formula, it will be about Rs. 25. I feel, Rs. 25 per quintal on an industry like *khandsari* is very high. The Finance Minister should really consider seriously whether we really want a small-scale industry to prosper in this country or not. I do not think that the Finance Minister is interested in helping the Indian sugar mills to exploit the farmers or the labourers. But still somehow the Finance Minister is granting concessions after concessions to the sugar mills while the small-scale industry like *khandsari* remains at the mercy of the big mill-owners. Therefore, I would request the Finance Minister to consider seriously to reduce the compound

levy to at least 20 per cent.

In U.P., as you all know, the State Government has imposed a levy of 25 per cent on *khandsari* industry. This particular aspect must be taken into account by the Central Government while imposing any Central excise duty at least in Uttar Pradesh.

These are the proposals that I would like to submit. I feel, if they are properly looked into, I do not see any reason why the *khandsari* industry cannot continue to play a vital role in consuming all the sugarcane which is not used by sugar mills after the crushing season.

In respect of the powerlooms, I know, the Finance Minister has been liberal enough to reduce the duties. Previously, from 1 to 4 powerlooms, the duty was Rs. 10; from 5 to 24 powerlooms, it was Rs. 75 and from 25 to 49, it was Rs. 150. Now, what you have done is, from 1 to 2 powerlooms, it is Rs. 50; from 2 to 4, it is Rs. 100 and from 4 to 49, it is Rs. 200. It means that a small man with 1 to 4 powerlooms will find it really difficult to survive. That is the real problem. We know that this small man having 1 to 4 powerlooms does not have the latest modern technology; he does not have the marketing facilities; he does not have the banking facilities; he does not have the technical know-how. I feel, these small people who are really in thousands in different parts of the country would suffer a great deal if the excise duty on powerlooms is not further reviewed.

Similarly, the Finance Minister has done nothing so far as *bidis* are concerned. *Bidi* industry is a very big industry in my area. There are a very large number of people engaged in this industry. I know that various Committees appointed by the Government, like the Venkatappaiah Committee, the Raghu Ramaiah Raghu Ramaiah Committee, have recommended to the

Government that in no case *bidi* should be taxed in this form. They have always recommended that it is tobacco which is to be taxed and whatever is to be done, it should be done, in the case of tobacco.

Again in the case of *bidi*, while the excise duty on tobacco has been reduced from Rs. 4.60 to Rs. 3, an additional excise duty of Re. 1 per thousand *bidis* has been imposed. This is 67 per cent increase in excise duty while the Government will have a very extensive control on *bidi* movement. This is a tobacco *purdiya* on which the Finance Minister has imposed excise duty. It will really be a job for tax machinery to find out exactly where it is being manufactured and where it is not being manufactured. This is an industry where more than 30 to 40 lakh people are engaged and they would really go out of employment if something drastic is not done so that this industry could survive....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please try to conclude.

SHRI VIRENDRA AGARWAL: I think, the time allotted to me is 30 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 20 minutes.

SHRI VIRENDRA AGARWAL: I will not go further on this because I do not have much time. I feel that the Finance Minister should do something about this *bidi* business.

The Union Government's Budget which totals up to Rs. 10,763 crores, an increase of Rs. 2,000 crores over the last year's Budget, it will mop up practically 20 per cent of the total national income in the country. We all know that inflation was not born yesterday; it has been creeping upon us as steadily as the size of the Budget has been growing.

We also know that a substantial part of our budgetary allocation is

eaten up by increase in nondevelopmental and non-plan expenditure. As the Budget documents indicate, the consumption expenditure increased by 17.3 per cent this year while capital formation, the amount that goes into building the sinews of growth, showed a rise of only 4.1 per cent. This means that the resources mobilised by the State under the name of Plan and Defence will, actually, be eaten up by the bureaucracy or end up in the bottomless pit known as the public sector.

What are we doing to improve the productivity of capital? I think we have reached the saturation point in our national history when the Government must ask itself seriously the question as to exactly to what extent are they able to put the capital to the best use. The bulk of the nation's capital today is locked up in the unprofitable public sector.

We all know that the national objective is growth with stability. But we want to know whose stability it is. Is it that of the economy or of the ruling Party? At the moment, the entire economic policy is such that one gets the impression as if the stability is needed, not of the economy or of the country, but of the ruling Party.

A disbursement of about Rs. 10,000 crores has been there. But the Finance Minister has not cared to mention anything about employment which, I feel is the most important national objective. The Finance Minister would do well to tell us and take the country into confidence as to what exactly would happen on the front of creating worthwhile employment for the people.

The present Government have no perspective, economic or social, and no deep commitment to growth or welfare. The entire fiscal system is hardly based on any valid social philosophy though the rulers are fond of talking about it. The Government, of course, is still groping in the dark.

[Shri Virendra Agarwal]

At the moment I feel that the economic system that they are trying to follow in this country has produced nothing but dishonest administration continues, we can never succeed either to revive the economy or to achieve economic Swaraj or full employment by the end of this Century.

श्री श्री कृष्ण अग्रवाल (महासमुन्द) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आप के माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश की जटिल समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस का विशेषकर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र सूखे से ग्रसित है। इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या आ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश शासन अपने साधनों के अनुसार इस समस्या को हल करने हेतु प्रयत्न कर रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में पानी की इतनी गम्भीर समस्या है कि अगर केन्द्रीय शासन द्वारा तुरन्त सहायता नहीं दी गई तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लोग प्यास से मरने लगेंगे। मनुष्यों के साथ-साथ पशु धन की भी बहुत बड़ी संख्या में हानि होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां पर पशु धन किसान की सब से बड़ी पूजी होती है, उसके नष्ट होने से देश के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे क्षेत्र का किसान पहले से ही बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, अगर पशु-धन का नुकसान हुआ तो इस नुकसान की कमी को वह जीवन भर कभी पूरा नहीं कर पायेगा। अतएव छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए केन्द्र को अति-शीघ्र ज्यादा से ज्यादा ट्यूब-वेल खोदने की मशीनें, जहां पर भी हों, जिस प्रदेश में भी हों, वहां से लेकर छत्तीसगढ़ में भेजनी चाहिए। वैसे हमारे मुख्य मंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती की है और उन से महाराष्ट्र में जो सिंचाई के काम में

मशीनें लगाई हैं उन्हें मध्य प्रदेश के लिए मांगा है इसे भी दिलाया जाय एवं चूंकि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दुःगम्भीर है, इस लिए यह बहुत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर शीघ्र जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा है। प्रदेश शासन द्वारा अपनी सुविधानुसार ज्यादा से ज्यादा प्रयास जनता को राहत पहुंचाने हेतु दिया जा रहा है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है।

राहत कार्यों में जो मजदूरी दी जाती है उस का रेट बहुत कम है। राहत कार्य की मजदूरी पुरुष को 2 रुपया 30 पैसा और स्त्री को 1 रुपया 70 पैसा दी जाती है। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों को मिला कर कोई 4 रुपए मजदूरी मिलती है। इन चार रुपयों में उन को अपनी जीविका चलाना अत्यन्त कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। यदि वे इन चार रुपयों में चावल ही खरीदना चाहें तो 2 किलो चावल भी नहीं मिलता है, तो फिर उन के परिवार की जीविका कैसे चलेगी। उन के लड़के, बच्चे, दीगर सामान—कपड़ा, दाल, साग आदि की व्यवस्था तो वे कर ही नहीं पायेंगे। अतएव मेरा अनुरोध है कि मजदूरी की दर जो राहत कार्यों के लिए दी जाती है उस को सरकार बढ़ाये। हमारे मध्य प्रदेश के शासन ने डिमाण्ड की है कि राहत कार्यों के लिए और ज्यादा केन्द्र से आर्थिक सहायता दी जाये। वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे प्रदेश की ओर वे विशेष ध्यान दें।

मैंने पहले भी कृषि विभाग की मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि कृषि विभाग द्वारा तुरन्त-वापस (इमीडिएट रिटर्न) योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रथम स्थान में चयन हुआ था। परन्तु आर्थिक अभाव के कारण यह कार्य हाथ में नहीं

लिया गया। हमारे देश में एग्रीकल्चर विभाग ने एक सर्वे किया है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाय ताकि उस का तुरन्त रिटर्न मिल सके। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ का इलाका प्रथम स्थान पर चुना गया। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ तुरन्त कुछ काम किया जाये, तो तुरन्त रिटर्न मिल सकता है। यह सौ करोड़ की स्कीम है। शिंदे साहब जब रायपुर में थे तो उन्होंने एनाउन्स किया था लेकिन फाइनेंस की कमी के कारण वह स्कीम रोक दी गई है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो अपने क्षेत्र की मांग को पूरा करने के बाद देश के अन्य प्रदेशों को लाखों टन चावल देता था वह आज खुद अपने लिए मोहताज है। आज उस क्षेत्र में खाने के लिए हम दूसरे प्रदेशों की ओर देख रहे हैं। अतएव वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है इस योजना को वे तुरन्त वहाँ लागू करें ताकि उस क्षेत्र की जनता को सहायता मिल सके।

जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो आयोग ने उस समय यह सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश चार राज्यों को मिलाकर बनाया जा रहा है और क्षेत्रफल में यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश होगा। देश का सबसे बड़ा और पिछड़ा हुआ प्रदेश होने के कारण इसकी आमदनी के जरिए कम है इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र इसके विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता करे। परन्तु केन्द्र द्वारा इस सिफारिश पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी भी हमारे प्रदेश में 3300 ग्राम 1500 से अधिक आबादी के हैं जो मुख्य सड़कों से जुड़े नहीं हैं। हमारे प्रदेश ने इस कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये की मांग की थी ताकि 1500 या 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सके परन्तु केन्द्र ने केवल 4-5 करोड़ रुपये ही दिए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिश की

थी उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार ने जो मांग की है उसकी पूर्ति की जाये। जब आवागमन के साधन ठीक रहते हैं तभी किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकता है। मेरा विश्वास है वित्त मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे।

हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खनिज पदार्थों का भण्डार है। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोह स्रोत आयरन-ओर का डिपॉजिट बैलाडीला है। बैलाडीला का माल जापान जा रहा है लेकिन उसके अतिरिक्त भी वहाँ पर बहुत आयरन-ओर है। मेरा निवेदन है कि भविष्य में यदि कोई लोहे का कारखाना खोला जाये तो वह बैलाडीला में खोला जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए वही उपयुक्त स्थान है। वहाँ से मात्र दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ेगा और इस प्रकार ट्रांसपोर्ट बचेगा। उसी प्रकार दूसरे धातुओं का भी हमारे यहाँ अपूर्व भंडार है। कोयले का जहाँ तक सवाल है, हमारे प्रदेश में कोयला बहुत है। हमारे यहाँ कोयले पर बेस्ट एक खाद के कारखाना का शिलान्यास आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कोरवा में किया था लेकिन मालूम नहीं कि किन कारणों से वह रोक दिया गया है। हमारे देश में खाद की बहुत ज्यादा मांग है। इस सब को देखते हुए भी जो कारखाना कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, वित्त मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे और उस कारखाने को जल्द से जल्द वहाँ चालू कराने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे देश में जो खाद की मांग है उस को पूरा किया जा सके।

15 hrs.

साथ ही कोयले पर बेस्ट बिजलीघरों को मध्य प्रदेश में लगाया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोयला ज्यादा है। देखा यह जा रहा है कि देश के दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर कोयला नहीं है, वहाँ पर बिजली घर लगाने की बात है। हमारे यहाँ से कोयला

[श्री श्री. रंग अग्रवाल]

वहां पर ले जाया जाएगा। वैसे ही दूसरे माल को ढोने के लिए बैगनों की कमी है रेलवे विभाग में और अगर कोयला हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को ले जा कर वहां बिजलीघर बनाए जायेंगे तो उस में और ज्यादा बैगन लगेंगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमारे प्रदेश में क्योंकि कोयला ज्यादा है इसलिए वहीं पर बिजलीघर लगाए जायें और नए कारखाने भी हमारे प्रदेश में लगाए जायें। इस से हमारे प्रदेश की बेकारी की समस्या हल होगी। इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश से लगे हुए जो दूसरे प्रदेश है उन की जो बिजली की जरूरत है, उन को जो कीमत बिजली उत्पादन में आती है उसी कीमत पर बिजली हमारा प्रदेश देगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश से कोयला न ले जा कर बिजलीघर हमारे प्रदेश में ही लगाए जायें और कारखाने स्थापित किए जायें।

इस साल बीड़ी पर जो एक रुपया प्रति हजार का नया कर लगाया गया है उस के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी उद्योग हिन्दुस्तान में सब से बड़ा लघु उद्योग है और हमारे देश के लाखों मजदूरों के जीविकोपार्जन का यह एक साधन है। यह जो टैक्स लगाया गया है इसको वसूल करने के लिए सरकार को अतिरिक्त मशीनरी रखनी पड़ेगी। और उद्योग से जो सम्बन्धित लोग हैं, उन को इस का हिसाब किताब रखने के लिए इस्टाब्लिशमेंट रखना पड़ेगा। टैक्स वसूल करने के बारे में मेरा कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक रुपए प्रति हजार का टैक्स बीड़ी पर न लगा कर बीड़ी के उपयोग में आने वाले तम्बाकू पर यह टैक्स बढ़ाया जाए। उस पर जो टैक्स लगा हुआ है उस को आप और बढ़ा दें और उस में बढ़ोतरी कर दें लेकिन बीड़ी पर यह टैक्स न लगायें क्योंकि इस से अलग से हिसाब रखने की व्यवस्था करनी होगी।

इसलिए यह जो परेशानी होगी, इस को दूर कर दिया जाए और मेरा विश्वास है कि हमारे मंत्री जी इस का ख्याल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और भी है कि पूरे देश में कुछ ऐसी आवश्यक चीजे हैं, जैसे कि चावल है, गेहूं है और मोटा कपड़ा है जो कि हरेक के काम में आती है, इन की कीमत पूरे देश में एक कर दी जाए। इस का फायदा यह होगा कि प्रदेशों में और जिलों में इन चीजों के आवागमन पर जो रोक लगी है और चीजों के भाव के कम या ज्यादा होने से जो स्मगलिंग होती है, उस से भ्रष्टाचार बढता है और कपटन होता है। उस को रोकने के लिए सरकार को अपनी मशीनरी लगानी पड़ती है। और शासन को भी परेशानी होती है और जनता भी परेशान होती है। मेरा यह सुझाव था कि इन चीजों के बारे में एक पालिसी बन जाए और पूरे देश में जो ये तीन चार आवश्यक चीजे हैं जैसे कि चावल, गेहूं, और मोटा कपड़ा, इन की कीमत एक हो जानी चाहिए पूरे देश में चाहे वह श्रीनगर से कन्या कुमारी तक हो या कहीं भी हो, सब जगह एक भाव में ये चीजे मिले ताकि लोगो को राहत मिले और भ्रष्टाचार कम हो।

एक चीज और कहना चाहूंगा और वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में है। इन पर एक परसेन्ट का टैक्स लगाया गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री वैसे ही बहुत परेशानी में है और हमारे यहां जो बड़े इंडस्ट्री वाले हैं उन से इन को कम्पीट करना पड़ता है। एम० एम० टी० सी० के द्वारा इन को इम्पोर्ट करना पड़ता है और उस में इन को 100, 200 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज के देने पड़ते हैं। उत्पादन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा कीमत पर होता है और बड़ी

इंडस्ट्रीज से इनको कम्पीट करना पड़ता है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक परसेन्ट जो टैक्स इन पर लगाया गया है, इसको वापस लिया जाए।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इरीगेशन पर बोलना चाहूंगा। हमारे देश के अन्दर कम इरीगेशन है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मेरी मान्यता यह है कि जितना भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम इनमें करते हैं एक वर्ष में, उसका रिटर्न हमको मिल सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा ध्यान इरीगेशन पर दिया जाना चाहिए और खास कर मेरे क्षेत्र में क्योंकि जहां पूरे हिन्दुस्तान में 20 प्रतिशत के करीब इरीगेशन है, वहां मेरे क्षेत्र में केवल तीन परसेन्ट के करीब यह है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) :
उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूँ कि माननीय सुब्रह्मण्यम साहब ने परसों जिन रियायतों की चर्चा की थी वे केवल कुछ बड़े घरों तक ही सीमित रह जायेंगे और ग्राम आदिमियों तक उन रियायतों की धारा नहीं जाने वाली है। अगर गिन्ती के हिसाब से भी जोड़ा जाए, तो इन्होंने जो 32.33 करोड़ रुपये की रियायतें दी हैं, इस देश की आबादी जो करीब 60 करोड़ के है, उसमें अगर इसको बांटा जाए, तो अठन्नी के करीब यह आएगी। तो यह केवल ग्रामका नोचने काका और खसौटने वाला क्लास ही होगा, जिसको वेस्टेड इन्ड्रेस्ट क्लस कहते हैं, जिसको यह पूरा भिजेगी और उसके पास ही यह स्कॉलरशिप जायेंगी और फिर ग्राम-ग्रामके बच्चे के बजट में इस प्रकार के लाभों और ग्राम आदिमियों से दूसरे तरीके से इसको क्लस लेवे। इस तरह से हम समझते हैं कि ग्राम आदिमियों को ही यह पूरा लाभ देना चाहते हैं।

हमको उम्मीद थी कि जब ग्राम वित्त

विधेयक पेश करेंगे, तो सरकारी खर्च में कहीं न कहीं कटौती की जाएगी। ग्राम-खोजों के दौरों पर, प्रधान मंत्री जी के दौरों पर जिस तरह से फ्रिजूलखर्ची ग्राम करते हैं, वह हम समझते थे कि कम होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो मालूम पड़ा है कि श्रीमती कमला बहुपुष्पा अभी विदेश का दौरा करके आईं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का छोटा प्लेन है, वह उनको दिल्ली से लखनऊ में गया और उसके बाद वही प्लेन उसी दिन लौट कर आया ग्राम के पार्लियामेंट या सरकार से सिविकम का बिल ले जाने के लिए। साथ-साथ वह बिल नहीं जा सका। आखिर प्लेन में पेट्रोल लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह फ्रिजूलखर्ची की मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। . . . (व्यवधान) . . . इस की चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री क्या करता है, ग्राम कहेंगे कि हम पर कैसे चर्चा करें, लेकिन फ्रिजूलखर्ची की बात मैं आपको बता रहा हूँ। केवल बिल लाने के लिए वह प्लेन यहां पर आया। मैं प्रधान मंत्री जी के खर्च के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि उनके एक-एक दौरे पर पांच-पांच लाख रुपया खर्च होता है। अब इस तरह की फ्रिजूलखर्ची पर ग्राम कहीं रोक नहीं लग रहे हैं और ग्रामने जो 33 करोड़ रुपये की रियायत खांडसारी पर और छोटी-छोटी चीजों पर दी है, हम समझते हैं कि ग्राम जनता को उससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जो व्याख्यात्मक टिप्पणी है बजट की, मैं उसको देख रहा था। जब मैंने इसको चारों तरफ देखा, तो मन में आया कि आखें मूंद लूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इन्होंने कर्ज लिया है जनता से, बैंकरोस की बात नहीं करता, और दूसरे देशों से, वह सारे का सारा कर्ज देखने के बाद हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको देखा जाए? ग्राम जनता को तो शायद पता भी नहीं है कि उसका कर्ज कहां इस समय कर्ज से लदा हुआ है और यह पैसा जाता कहाँ है? यह पैसा इनका सामंजस्य की-बोजों में खर्च होगा है। कर्ज से कर

यह सरकार क्रम्बारा बनाया करती है चाहे यह कौन्ट प्लेस में क्रम्बारा लगा हो या अरि कहीं। सिचार्ड के लिए जमीन खाली रह जाएगी और किसान पानी के लिए चिल्लाते रहेंगे और यह कहते रहेंगे कि बिजली नहीं है, नलकूप नहीं है, रिगिंग मशीन नहीं है वगैरह, लेकिन पूरी दिल्ली में क्रम्बारे लगाए जा रहे हैं और दिल्ली ही नहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में उसकी नकल हो रही है और छोटे शहरों में भी यही बात है। तो केवल इनका पैसा शान-शोकत पर खर्च होगा और दूसरे कामों पर खर्च नहीं हुआ करता है।

इस तरह से इनकी फ्रिजूलखर्ची इतनी तेजी से बढ़ती है और अपने बजट भाषण में यह कहते हैं कि विपदा है, आफतें आई हैं और प्राकृतिक विपदाएँ हैं। एक बार विपदाओं का बराबर बंटवारा कर देते, तो ग्राम जनता को तसल्ली हो जाती लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं। मैं कार की चर्चा करूँगा। पिछले तीन-चार साल के एक प्रकार की गाड़ी की बहुत चर्चा हुई है और यहां ही नहीं हुई देश भर में हुई है। छः दरवाजे वाली गाड़ी, विदेश से आई थी और राष्ट्रपति भवन में पड़ी है। गर्मियों के दिनों में यह ठंडी हो जाती है और जाड़े से गर्म हो जाती है। वह कार ऐयाशी के निशानी है और उसका आपके बजट में स्थान दिया गया है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ छोटी कार की चर्चा होती है जो अभी बन नहीं पाई है। एक तरफ छः दरवाजे वाली कार जो ऐयाशी की निशानी है और दूसरी तरफ छोटी कार का कारखाना जो अष्टाचार की निशानी है। सरकार और व्यापार की सांठगांठ। जिस मंत्री का बेटा अगर उनसे साइसेंस के ले. ए. है तो यह तय है कि कहीं व नहीं किसी न किसी कोने में अष्टाचार आया है, उसके जरिये न आए, उसके सचिव के जरिये आया, दूसरे अधिकारियों के जरिये आया। एक तरफ तो ऐयाशी की निशानी, छः दरवाजे वाली कार और दूसरी तरफ

अष्टाचार की निशानी यह छोटी कार है। दोनों तरफ की व्यवस्था करना हम अगर छोड़ते नहीं हैं तो जो कोई भी बजट पेश करे, जितना बढ़िया पेश करे, जितनी कारबलियत से डाफ्ट करके पेश करे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तब अष्टाचार केवल छोटी कार तक जाकर सीमित नहीं कर पाएगा उसके रिश्ते बनते चले जायेंगे। श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने भाषण में जिदल की चर्चा की थी और कहा था कि इसके शेर मारुति कार में हैं। आपको क्या हक है कि कौन्सिल सरकार की तरफ से आप उन लोगों को दें। अब जो जो कन्सेशन दिए जाते हैं उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लिये साहब ने मोदी ग्रुप के बारे में चर्चा की थी। बिड़ला साहब के बारे में चर्चा हो जाती है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अर्थ व्यवस्था में जहां कंटे, परमिट और लाइसेंस प्रणाली में सरकार का व्यापार के साथ रिश्ता रहता है, वहां अष्टाचार तो आएगा ही। उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं इस पर आप ईमानदारी से गौर करें। अभी तक सरकार ने गौर नहीं किया है।

मैं बिड़ला का नाम लेता हूँ। बिड़ला का एक कारखाना जि. जौपुर में है हिंडालको। उस कारखाने के मजदूरों का अ. बोलत होने वाला था। कारखाने के कुछ अधिकारी दिल्ली में आए। उन्होंने प्रधान मंत्री के सचिवालय में सम्पर्क किया। सम्पर्क करने के बाद कोठारी साहब जो हिंडालको के भासिक हैं उनकी पत्न लिखा कि हमने प्रधान मंत्री के सचिवालय से सम्पर्क किया है और उनके प्राइवेट सिक्रेटरी को हमने पांच लाख रुपये दिया है और प्राइवेट सिक्रेटरी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हिंडालको में कोई लेबर ट्रबल नहीं होगी। उस बिड़ली की छत्ती हुई कभी केरे पास है। यह अष्टाचार का निशानी

है। मैं इसको पढ़ देता हूँ :

"To

Shri S. S. Kothari,
President, HINDALCO,
Renukoot.

Dear Sir,

We met the Prime Minister and her Private Secretary. We have paid a sum of Rs. Five lakhs to the P. S.

He has promised us that he will use all his influence to see that no trade union activity is allowed in Hindalco.

Yours faithfully,

For Hindustan Aluminium Corporation Ltd.

THE MINISTER OF FINANCE
(SHRI C. SUBRAMANIAM): Kindly pass it on; let me have a look at it.

श्री जनेश्वर मिश्र : आपको तो दे ही देता हूँ और अगर आप कहें तो इसको मैं टेबल पर भी रख देता हूँ।

हिंडालको में हम लोगों की यूनियन बहुत कमजोर है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की यूनियन वहां मजबूत है। इन लोगों को यूनियन वालों की पिटाई कराने के लिए श्री कोठारी ने वहां के पुलिस अधिकारियों की मदद ली जिसमें एक डी०एस०पी० तक मारा गया। जब पांच लाख रुपया लेकर ट्रेड यूनियन को क्रश करने का आप प्रा मित्र करेंगे, पुलिस की तरफ से ज्यादाती करवाएंगे तो उस तरह की घटनाएं ही घटेंगी जो दस दिन पहले घटी थी कि एक डी०एस०पी० भी मारा गया था ट्रेड यूनियन मूवमेंट के चलते। यह हिंडालका का किस्सा है।

ऐसा ही सिंघानिया का भी किस्सा है। उसके स्मथर्स के साथ साठ-गांठ थी और उस साठ-गांठ के सिलसिले में जूट वैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेजीडेंट श्री एच० के० सिंघानिया के खिलाफ मिसा में वारंट निकला। वह बंडरगाउंड हो गए। उसके बाद वह दौड़े हुए दिल्ली आए। यहाँ आकर उन्होंने

प्रधान मंत्री से सम्पर्क किया। पचास लाख रुपये पर सौदा पट गया और उनके खिलाफ वारंट खत्म हो गए। यह सरकार भ्रष्टाचार के किस रास्ते पर जा रही है। सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार बेईमानी आदि के जितने आरोप आज लग रहे हैं क्या उसका असर देश के चरित्र पर नहीं पड़ता है। श्री विभूति मिश्र ने भाषण किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी बोलो, सरकार पर असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि इतना जबर्दस्त बहुमत उनकी पार्टी को मिला है लेकिन फिर भी उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इतना होने पर भी जब बटन दबा ना होगा तो उन्हीं के पक्ष से ये दबायेंगे। क्यों नहीं ये लोग अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, क्यों ये अपने फर्ज को पहचानते नहीं हैं। कभी-कभी ये खिलाफ भी बटन दबा दिया करें। मैं कान दबाने की बात नहीं करता हूँ, बटन दबाने की बात कर रहा हूँ, टेबल का बटन। जब मिश्र जी की बात मैं सुन रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि इनका मनबड़ा दुखी है, बड़ा दर्द से भरा हुआ है। इतने पुराने ये कांग्रेस के सदस्य हैं और इस सदन में हैं लेकिन फिर भी इनको लगता है कि हम बेकार यहाँ हैं।

इन सारे भ्रष्टाचारों के किस्सों के बाद अब मैं खेती पर आता हूँ। मैं खास तौर पर उर्वरक की चर्चा करूंगा। एक उर्वरक कारखाना आपका गोरखपुर में चल रहा है और एक इलाहाबाद में फूलपुर में चलने वाला है। आप उर्वरक के भाव को देखें। छः महीने पहले खाद 53 रुपये बोरी मिलती थी किसान को और आज 105 रुपये बोरी मिल रही है। एक बोरी में खद पचास किलो होता है। किसान को आप महंग का भाव 105 रुपये किबटल देते हैं। एक किबटल खाद की कीमत 210 रुपये हो गई। अब खाद की कीमत तो 210 रुपये किबटल और गेहूँ की बोरी की कीमत 105 रुपये किबटल। किसान का पिछले दो महीने पहले गेहूँ 200-225 रुपये के भाव से बिका है। आपने थकबीक फरमान जारी कर दिया कि

[श्री जनेश्वर मिश्र]

किसान को 105 रुपये का भाव मिलेगा। भावने कहा कि इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है। श्री जगजीवन राम ने कहा कि बच्पर आप है। श्रीमती इंदिरा गांधी बम्बई गईं वहाँ औरतों ने काले झंडे ले कर उनको घेर लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने काले झंडे लिए हुए हैं इन्होंने ही रेलवे की हड़ताल कराई थी जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। फिर कहती हैं आज से चार महीने पहले कि बबराओ मत, रबी की फसल बढ़िया आ रही है, महंगाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद सुब्रह्मण्यम साहब और श्री फखरीन अली अहमद साहब ने भी आम जनता के बीच कहा कि रबी की फसल बढ़िया आ रही है, महंगाई खत्म हो जाएगी। आज किसान को गुस्सा है। जो जायज भी है। उड़ीसा में जब राज्य सरकार की पुलिस पार्टी लैबी बसूल करने गई तो सात किसान उसको गोली के शिकार हो गये। वे अड़े हुए हैं कि लैबी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि भाव तय करने का हक आपको नहीं है। अगर कारखानों में बनी चीजों के दाम आप उसी हिसाब से नहीं घटाते हैं जिस हिसाब से खेती की चीजों के दाम घटाते हैं तो किसान आपको आपके भाव पर अपने माल को क्यों दे। 105 नहीं, 90 रुपये भाव आप कर दें किसान तैयार हैं लेकिन 103 या 105 रुपये बोरी खाद का जो भी दाम है उसको भी तो आप उसी हिसाब से, उसी अनुपात से कम करें। मौजदा सरकार बोट तो लेती है किसान से और चन्दे लेती है कारखानेदारों से। कारखानेदारों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम तो आप कम नहीं करते हैं, लेकिन किसान बेचारा जो आपको चन्दे नहीं देता है केवल बोट देता है उसके उत्पादन पर आप लगातार रोक लगाते चले जा रहे हैं। आज भी आप गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले साल आपने 76 रुपये किसान भाव तय किया था गेहूँ का जबकि

बाजार में वह 225 रुपये तक बिका। अब भी आप गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हैं कि 105 रुपये का जो भाव आप किसान को देंगे और इस भाव पर उससे गेहूँ बसूल करेंगे वही गेहूँ अगली फसल आने तक बाजार में किस भाव पर बिक पाएगा। यह गारंटी देने के लिये वित्त मंत्री, कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम जी, या प्रधानमंत्री कोई भी तैयार नहीं हैं। किसान अपना गेहूँ सस्ते भाव पर बेचे और तीन महीने के बाद जब वह उसे खरीदे, तो महंगे भाव पर खरीदे। इस प्रकार से उसको दोनों तरफ घाटा होता है। अगर किसान के गेहूँ का भाव सरकार को तय करना है, तो फिर उर्वरक का भाव, बिजली का रेट, और दूसरी चीजों के दाम भी उसी हिसाब से तय करने चाहियें।

इसके साथ-साथ सरकार अपनी फिजूल-खर्ची को भी कम करे। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसान का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाये और वहाँ टाट न होने की वजह से उसे बोरा लेकर जाना पड़े और दूसरी तरफ देहरादून तथा ऊटी के स्कूल उसी तरह से चलते रहें। तब तो किसान के मन में यह भावना आयेगी कि जो गेहूँ वह पैदा करता है, उसको वह इतने ज्यादा दाम पर बेचे ताकि उस का बेटा भी कभी देहरादून या ऊटी के स्कूल में जाकर पढ़ सके। आदमी के मन में यह लालच स्वाभाविक होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार और उसके मंत्री अपनी मानोशौकत और फिजूल-खर्ची में भी कमी करें। अगर मंत्रियों के बच्चों और किसानों के बच्चों को एक जैसे स्कूल में भेजने की व्यवस्था हो जाये, तो उसमें क्या खराबी है ?

जब कभी यहाँ बहुत लक्ष्मी है कि बढ़िया चाहे स्कूल खत्म करो और एक

जैसे स्कूल स्थापित करो, तो जवाहरलाल भी के जमाने से लेकर आज तक एक ही बात कही जाती है कि अगर ये देहरादून, ऊटी और नैनीताल के स्कूल तोड़ दिये गये, तो लायक लड़के कहां से आयेंगे, यानी देहरादून, ऊटी और नैनीताल में पढ़ने वाले लड़के लायक होते हैं और म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के नालायक होते हैं। उन बच्चों की नालायकी हम जानते हैं। वे बैठे रहते हैं, किसी को तड़ी मारते हैं, किसी को चिकौटी काटते हैं। मान लीजिये कि उन्हीं लड़कों की बगल में श्री सुब्रह्मण्यम का बेटा और प्रधान मंत्री का पोता, राहुल भी बैठकर पढ़ता, तो गांव के टैक्सी वाले का लड़का उनको तड़ी मारता और चिकौटी काटता। शाम को जत्र मंत्री महोदय का लड़का उनकी गोद में आता, तो वह उनको भी तड़ी मारता और प्रधान मंत्री जी का पोता उनकी गोद में आता, तो वह उनको चिकौटी काटता। तब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से लेकर मंत्री महोदय और बड़े-बड़े सरकारी अहलकार तक यह सोचने को मजबूर होते कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिये, वरना हमारे बच्चे भी बिगड़ जायेंगे।

अगर सरकार लेवी का सस्ता भाव तय करना चाहती है, तो उसी हिसाब से कारखाने के उत्पादन के दाम भी कम करने चाहिए। तभी किसान सरकार पर थकीन करेगा, वरना नहीं, और जिस तरह से आज वह लेवी के सम्बन्ध में अड़ा हुआ है, आगे भी वह अड़ा रहेगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि पंजाब में इस सभ्य गेहूं सस्ता होता चला जा रहा है। ठीक है, तो सरकार जाकर खुले बाजार में खरीद ले। लेकिन वह कानून के बल पर जबर-दस्ती क्यों खरीदना चाहती है, यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया है।

हम देखते हैं कि जब कोई भी प्रश्न उठाया जाता है, चाहे वह लेवी का ही या बच्चों की शिक्षा का, तो बड़े जोर से हुस्ला मधता है कि संसदीय लोकतन्त्र को खतरा है। अभी सत्तारूढ़ दल के एक दो सदस्य वित्त विधेयक पर बोलते हुए भी श्री जयप्रकाश नारायण के भ्रान्दोलन को बीच में ले आये। मेरा कहना यह है कि वित्त विधेयक पर श्री जयप्रकाश नारायण की चर्चा बेमतलब खाने की क्या जरूरत है ?

ला एंड ग्रांडर के नाम पर एक टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसमें विरोधी पार्टियों के लोगों को तोड़ने के लिए एक सैन बना हुआ है। उस पर सरकारी पैसा खर्च हो रहा है और उसकी सीधी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री पर है, अगर ला एंड ग्रांडर के नाम पर इसी तरह मुल्क का पैसा खर्च करना है, तब तो मैं समझूंगा कि यह बिल्कुल खतरनाक बात है।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : अगर माननीय सदस्य चिकौटी काटने की प्रक्रिया को अपने घर में शुरू करें, समाज में शुरू न करे, तो बेहतर होगा।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह सरकार बेईमानी की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और राजनीतिक बदचलनियों की सरकार है और इसीलिए इस सरकार को वित्त विधेयक पास करके देश की आम जनता की कमाई का पैसा देना सांप के मुंह में जहरीला दांत देना है। इस लिए मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को गिरा दे, पास न करे।

श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुये मंत्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि जो नीति उन्होंने अपनाई है, उससे वह सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह पूंजीवादी नीति भी नहीं है और समाजवादी नीति भी नहीं है और वह दोनों के बीच में चल रहे हैं।

अमरीका के लोग श्री जयप्रकाश नारायण और दूसरे लोगों के बल पर देश में भ्रराजकता

और अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आज पूँजीपति हमारे देश के जीवन को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं। बड़े-बड़े आदमी गरीबों को सताते हैं और उनका दमन करते हैं। आज सरकार को एक रास्ता अपनाना चाहिए और वह रास्ता है रूस का। सारी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारी समस्या हल नहीं होगी। अगर हम किसी पूँजीपति का कान काट लें या नाक काट लें, तो वह दुश्मन बन जाता है। अगर पूँजीपतियों को खत्म करना है, तो उनको जड़ से ही खत्म करना चाहिए, तभी देश का कल्याण होगा।

हमारे देश में सरकार का खर्चा ठीक ढंग से नहीं होता है। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करते हैं। क्या वे किसी गरीब के साथ न्याय करते हैं? एक गरीब दो रुपये में दिन भर मिट्टी खोदता है, जबकि वकील लोग काला कोट पहनकर दो दो हजार रुपये लेते हैं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? हर पार्टी के आदमी लोगों को लूट रहे हैं। हम भी लूट रहे हैं। हम 50 रुपये राज पाते हैं, लेकिन सेंट्रल हाल में बैठकर गप्प लड़ाते रहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि जिले की अदालतों को खत्म कर दिया जाये और गांव पंचायतों तथा जिला परिषदों को न्याय का अधिकार दिया जाये। उसी तरह हाई कोर्ट को खत्म कर दिया जाये और विधान-सभाओं को कुछ मामलों में अधिकार दिये जायें। सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म करके लोक-सभा के सदस्यों को अदालत के अधिकार दिये जाये। यह भी आवश्यक है कि कार्बल आदमियों को चुनाव में लिया जाये और चुनाव पद्धति को बदला जाये। इस चुनाव पद्धति में चुनाव में लाखों रुपये खर्च होते हैं। हर पार्टी में टिकट लेने वालों का मेला सा लग जाता है। हम लोग बातें करते हैं

समाजवाद की, लेकिन हम सारे काम पूँजीवाद के करते हैं।

राष्ट्रपति, राज्यपाल और कलेक्टर आदि जिला अधिकारियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा हो। प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और जिला परिषद् के चेयरमैन को खत्म किया जाये। जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो और वही अपनी गवर्नमेंट बनावे। इस तरह से खर्चा बहुत कम हो जायेगा जब हमारे देश में लाखों आदमी भूखे मर रहे हैं तब हम लोग क्रिकेट के खेल का आयोजन करते फिरते हैं, जगह-जगह टेली-वीजन लगाते फिरते हैं और नंगी औरतों को नचाते हैं। क्या इससे समाजवाद आयेगा? क्या इससे गरीबी मिटेगी? हमें गरीबों को नहीं मिटाना है, अमीरों को मिटाना है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहती हैं, मगर वह पूँजीपतियों के विरोध के कारण, जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर नाच रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। हमें उन पूँजीपतियों का मुकाबला करना है। मंत्री महोदय का क्या दोष है। अगर हमारी नीति ठीक होती, तो हम अपने देश से गरीबी को दूर करके समाज की स्थापना कर सकते थे।

जिस किसी धर्म के ग्रन्थ में ऊंच-नीच के भाव हों, उस ग्रन्थ को बन्द कर देना चाहिए। आज हमारे यहां धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर, जात-पात के नाम पर, लूट होती है। आखिर धर्म क्या है? भगवान एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। उसको गौंड, भगवान और खुदा कह सकते हैं। अगर अलग-अलग भगवान हैं, तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा कि कौनसा भगवान ठीक है। अलग-अलग धर्मों के नाम पर जो सम्पत्ति इकट्ठी की गई है, उसको जब्त कर लेना चाहिए। अलग-अलग धार्मिक

संस्थाओं के पास जो जमीन है, उसको लेकर उस पर गत्ता पैदा किया जा सकता है।

आज सबेरे जब मैंने सुना कि 30 हरिजनों को जला दिया गया है, तो मुझे रोना आ गया। मैं सोचता हूँ कि जिन नब्बे प्रतिशत गरीबों और हरिजनों से हमको यहां भेजा है, आज उनको जलाया जात है। गृह मंत्री महोदय इसके बारे में ध्या कर रहे हैं? एक बार बिहार में जब तीन आदमियों को जला दिया गया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री मिर्धा को विमान से वहां भेजा था। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री भी घटना स्थल पर जाये। वह हम का इजाजत दें, कि हम जाकर जांच करें कि कैसे यह जुल्म और ज्यादती होती है।

दूसरी पार्टियां तो पूंजीपति हैं ही। यद्यपि हम ऊपर से समाजवादी हैं, मगर भीतर से हम भी पूंजीवादी हैं। बड़े-बड़े कांग्रेसमैनों की जायदादों को जब्त क्यों नहीं कर लिया जाता ?

पहले जमाने में राजा लोग टोपी सीकर या हल जोतकर खाते थे। वे राजघन का प्रयोग अपने लिए नहीं करते थे। मैं सन्यासी हूँ। मैं भी भिक्षा से अपना निर्वाह करता हूँ और अपनी सारी तनख्वाह का पैसा स्कूल, कालेजों को दे देता हूँ। यही धर्म है।

आज स्कूलों में क्या हालत है? शिक्षक 7 दिन में 3 घंटे पढ़ाते हैं और 1200 रुपये वेतन लेते हैं। आज छोटे स्कूलों की स्थिति यतीमखाने जैसी हो गई है। बड़े आदमियों के लड़के देहरादून में पढ़ते हैं। इस स्थिति में क्या कोई गरीब आदमी लड़का कभी कलैक्टर या उच्चाधिकारी बन सकेगा? आज जो आदमी ऊंचे पदों पर बैठे हुये हैं, वे गरीब आदमियों का कल्याण कैसे करेंगे?

गांधी जी ने कहा था कि किसी हरिजन की लड़की के राष्ट्रपति बनाया जाये। अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है? अगर हम लोग गांधीवादी हैं, तो किसी मेहतर की लड़की को

राष्ट्रपति बनाना चाहिए। हरिजनों और मेहतरों में से एस० पी० और कलैक्टर बनाये जायें। अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो, तो उन लोगों को सजा दी जाये।

क्लर्क और दूसरे लोग 8 घंटे काम करते हैं। हमारे किसान सारा दिन हल चलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सदस्य सभापति के आसन पर बैठते हैं, वे केवल दो घंटे काम करते हैं और उसके बाद खिसक जाते हैं। क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ दो घंटे की है? यह भी भ्रष्टाचार है।

मेरे पांव में दर्द होता है, इसलिए मैं इस ठंडक में नहीं बैठ सकता हूँ, वरना मैं सारे दिन यहां बैठा रहूँ। जब मुझे 51 रुपये रोज मिलते हैं तो मैं क्यों न सारा दिन यहां पर हाजिर रहूँ ?

मेरे कालेज का एक लड़का डा० सी० एल० इदीवर यादव विश्व भर में 9 लाख प्रतियोगियों में से अध्यात्म और विज्ञान में पहले नम्बर पर आया। लेकिन उसको कोई सम्मान नहीं दिया गया, जबकि खेल वालों का सम्मान हो रहा है। क्या खेल से ही गेहूँ निकलेगा, या दूध निकलेगा, या टेलीवीजन से दूध निकलेगा? यह सब काम बन्द करके सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। किसानों पर तो सीलिंग लगा दी गई है, लेकिन पूंजीपतियों पर कोई सीलिंग नहीं लगाई गई है।

15.35 hrs.

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 46)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संसद घन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 2-5-75.